कृषि   विश्लेषण   जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रू.

ज्येष्ठ-आषाढ़ 2080, जून 2023

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये में निपटान

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

प्रांतीय कार्यशालाएं व विचार वर्ग

सचित्र झलक

कानपुर प्रांत

उत्तराखंड प्रांत

गोरक्ष प्रांत

बैठक, रोजगार सृजन कैंद्र, गया (बिहार)

7 दिवसीय कार्यशाला - त्रिपुरा प्रांत

स्वदेशी पत्रिका

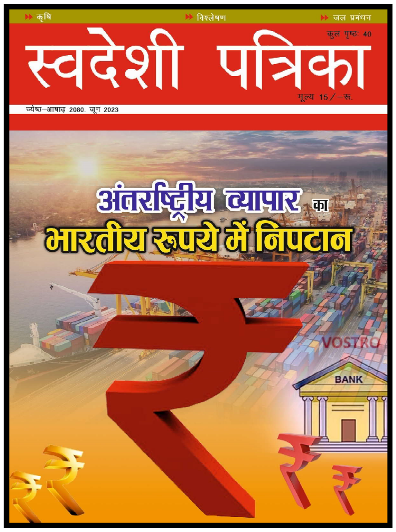

वर्ष–31, अंक–6
ज्येष्ठ–आषाढ़ 2080 जून 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अ नु क्र म

आवरण कथा – 6

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये में निपटान

स्वदेशी संवाद

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आर्थिकी
सही है दो हजार के नोट की वापसी का निर्णय
.... डॉ. अश्वनी महाजन

10 अर्थव्यवस्था
नकली नोटों से असली तबाही
.... अनिल तिवारी

12 खाद्य सुरक्षा
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जूनः आहार, आरोग्य और अर्थतंत्र
.... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

15 मुद्दा
'यमुना कालिंग' भविष्य की आवाज
.... राजकुमार भाटिया

17 विश्लेषण
मोदी सरकार के नौ सालः काम अधिक, बातें कम
.... केके श्रीवास्तव

19 विमर्श
नयी दिल्ली से टकराव की नित नयी जमीन तैयार करता बीजिंग
.... विक्रम उपाध्याय

21 स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण
.... डॉ. जया कक्कड़

23 मुद्दा
देश के विकास एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है समान नागरिक संहिता
.... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

25 जांच–पड़ताल
सुलग रहा मणिपुर
.... विनोद जौहरी

28 बीच–बहस
वित्तीय समावेशन से भारत में गरीब वर्ग का हो रहा कायाकल्प
.... प्रहलाद सबनानी

30 स्वदेशी गतिविधियां
राष्ट्रीय परिषद बैठक, पुणे (महाराष्ट्र)
.... स्वदेशी संवाद

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

पाठकनामा

विश्व पर्यावरण दिवस

हर साल 5 जून को समूचा विश्व 'पर्यावरण दिवस' मनाता है और बदलती जलवायु की समस्या से पार पाने के लिए सार्थक और सटीक उपाय करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता जाहिर करता है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग (बढ़ते वैश्विक ताप) का सामना कर रही है। तमाम कारण गिनाए गए हैं, जिन्हें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। बेशक यह कारण मानव व्यवहार से ज्यादा बाबस्ता है, लेकिन हम ऐसा कोई कारगर उपाय नहीं खोज पाए हैं, जिससे इस समस्या से उबर सके। विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि वैश्विक ताप में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी का यह रुझान बना हुआ है। बताया जा रहा हैं कि एक–दो सेंटीग्रेड भी तापमान बढ़ा तो गेहूं जैसे खाद्यान्न तो गायब ही हो जाएंगे। देश में मानसून की दस्तक पर असमंजस के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम की आंख मिचौली चल रही है। मई के महीने में रुक–रुक कर सावन जैसी बरसात ने लोगों को गर्मी के महीने में ठंड का एहसास तो दिया लेकिन किसान के पेशानी पर चिंता की लकीरें भी उभार गई। वैशाख–जेठ के महीने की गर्मी खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। गर्मी के कारण फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े लगभग मर जाते हैं और मानसून की बारिश होने पर वह खाद का काम करते हैं। इस बार रुक रुक कर बरसात होने और कई इलाकों में खेतों में पानी भर जाने के कारण गर्मी की जुताई भी नहीं हो सकी है।

विकास की तीव्र आधी में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का मुख्य आधार आज भी कृषि है। साफ है यदि प्रकृति के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे तो कृषि पर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ता जाएगा, जिससे अधिकांश जनसंख्या के लिए रोजी–रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। वर्ष 2030 तक भूख को खत्म करने का हमारा लक्ष्य भी अधूरा रह सकता है। मालूम हो कि हमारे देश के अधिकांश किसानों के पास खेती का रकबा बहुत छोटा है इसलिए इस तरह की आपदाओं के कारण उनकी आमदनी लगातार कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ कृषि के लिए बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए भी खतरे के रूप में सामने आ रहा है कोई भी देश इसकी आंख से बच नहीं सकता। इसलिए हमें अविलंब जलवायु का ऐसा विखंडन रोकने के लिए आगे आना ही होगा ताकि समय रहते मानवता की रक्षा की जा सके।

डॉ. पराक्रम सिंह धुंधरी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः **swadeshipatrika@rediffmail.com**

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

मध्यम वर्ग विकास और नवाचार को चलाने में सबसे आगे है। उनकी मेहनत नए भारत की भावना को परिभाषित करती है। हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में लगातार काम किया है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

सभी वैश्विक मंच... यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने पर सहमत हो गए हैं। हमारा मॉडल प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण का है जबकि अमीर देशों का मॉडल दूसरा है जिसमें तकनीक कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के हाथों में है।

अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री, भारत

पर्यावरण के प्रति जागरूकता हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए मिशन लाइफ को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

भूपेन्द्र यादव, श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत

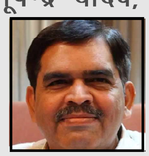

रुपये में व्यापार निपटान को मंजूरी देने के ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और उपाय किए जाने चाहिए। इनमें अधिक से अधिक देशों को व्यापार मुद्रा के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करके ऐसा कर सकता है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी हैं मंदिर और तीर्थस्थल

हाल ही में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े एक टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा ने कहा है कि मंदिर रोजगार पैदा नहीं करते। स्वभाविक तौर पर वर्तमान में मंदिरों के प्रति आग्रह के संदर्भ में उनकी टिप्पणी रही होगी। सैम पित्रोदा चाहे कुछ भी कहें, मंदिरों का अर्थशास्त्र समझने की आज बहुत जरूरत है। हमें समझना होगा कि धार्मिक सेवाओं और मंदिरों का भी अपना एक अर्थशास्त्र होता है। मंदिरों से भी भारी रोजगार सृजन होता है। मंदिरों के आसपास असंख्य लोग अपना जीवनयापन करते हैं और मंदिरों में भी आधुनिकीकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से न केवल उन सेवाओं के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि जीडीपी में भी उनके योगदान में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की ही भाँति मंदिर अर्थव्यवस्था के बारे में भी चिंतन और विचार करना जरूरी है। हम देखते हैं कि भारत में कई शहरों और कस्बों की एक बड़ी आबादी तो अपनी जीविका के लिए सिर्फ मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों पर ही निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मथुरा–वृंदावन, अयोध्या, कुशीनगर, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर प्रसिद्ध हैं। यदि हम देखें तो लगभग सभी राज्यों में एक या एक से अधिक बड़े धार्मिक केंद्र हैं। तमिलनाडु में मदुरै का मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम मंदिर और कई अन्य मंदिर हैं। उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ मंदिर; गुजरात में सोमनाथ और द्वारका, पंजाब में स्वर्ण मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है; झारखण्ड में देवघर में बैद्यनाथ मंदिर और रांची में जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं; मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल मंदिर और भारत के कई शहरों– क़स्बों में कई मंदिर हैं, जो भारत भर में आस्था के केंद्र हैं। जिन शहरों में ऐसे मंदिर स्थित हैं, वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और सैलानियों का आना होता है। कई स्थान तो ऐसे हैं, जहां एक ही दिन में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। जम्मू के पास कटरा में स्थित अकेले वैष्णो देवी मंदिर में ही वर्ष 2022 में 91 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तमिलनाडु के पास आंध्र प्रदेश में स्थित तिरूपति मंदिर में 2022 में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी प्रकार से अलग–अलग मंदिरों में करोड़ों लोग हर साल दर्शन करने जाते हैं। यह स्वभाविक धार्मिक पर्यटन हमारे कुल पर्यटन व्यवसाय का एक बड़ा भाग है, जिससे बड़ी मांग का सृजन होता है। अनुमान है कि भारत में कुल धार्मिक पर्यटन का हिस्सा कुल घरेलु पर्यटन में 60 प्रतिशत है, जबकि 11 प्रतिशत विदेशी सैलानी धार्मिक उद्देश्य से आते हैं। गौरतलब है कि भारत की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा लगभग 7 प्रतिशत है और देश के कुल रोजगार में इसका हिस्सा 8 प्रतिशत है। यानि यह क्षेत्र 3. 9 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में कुल घरेलु पर्यटन में जहां धार्मिक पर्यटन का योगदान 60 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 11 प्रतिशत होने के कारण मंदिरों के भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता।

वर्तमान में बन रहे भव्य श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्र और उज्जैन के महाकाल मंदिर में हो रहे विकास से आशा की जा रही है कि इन स्थानों पर अब ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। कई मामलों में, ये धार्मिक शहर विवाहों के लिए गंतव्य भी हैं, जो इन शहरों के निवासियों के लिए रोजगार और आय का एक अन्य स्रोत है। मंदिर केवल अपनेआप के लिए ही नहीं, उनके आसपास के क्षेत्रों के लिए भी काफी लाभकारी होते हैं। इन सभी धार्मिक केन्द्रों के कारण इन सभी शहरों में काफी ज्यादा आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अधिकांश व्यापार, यातायात, धार्मिक अनुष्ठान और संबंधित गतिविधियां इन केन्द्रों पर इन मंदिरों के कारण ही संचालित होती है। केवल मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों के ही नहीं, बल्कि व्यापार, यातायात और उद्योगों में बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होता है।

समझा जा सकता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि मंदिरों से रोजगार निर्माण नहीं होता अथवा मंदिरों का भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है, वे इन तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। हमारे पास कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कई मंदिर, तीर्थ स्थान, धार्मिक और आध्यात्मिक विभूतियाँ शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना में अनुकरणीय कार्य कर रही हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में हिंदू मिशन अस्पताल की स्थापना 1894 में हिंदू मिशन सोसाइटी द्वारा की गई थी। यह देश के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक है। राम.ष्ण मिशन पूरे भारत में कई शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य केंद्र चलाता है। आर्य समाज भी पूरे भारत में कई शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य केंद्र चलाता है। इनमें स्कूल, कॉलेज और अस्पताल शामिल हैं।

भारत में जैन मंदिर परंपरागत रूप से शिक्षा के केंद्र रहे हैं। कई जैन मंदिरों में पुस्तकालय, स्कूल और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय भी हैं। भारत में सिख गुरुद्वारे भी देश को मुत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिक एवं तीर्थ पर्यटन की संभावनाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों का विकास करते हुए देश के विकास में इनके योगदान को बढ़ाया जाए। इस हेतु मंदिरों का जीर्णोद्धार, सस्ते और महंगे सभी प्रकार के होटलों का निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं का विस्तार और इन केन्द्रों में पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना और इन तक पहुंचने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के साथ उनका जुड़ाव आदि कुछ ऐसे कार्य हैं, जिसके द्वारा इन तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुष्ट किया जा सकता है।

राष्ट्रीय परिषद बैठक, पुणे (महाराष्ट्र) में जारी वक्तव्य

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये में निपटान

जुलाई, 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक परिपत्र के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के भारतीय रुपये में निपटान की अनुमति दी थी। यह यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते रूस को भुगतान के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में एक रणनीतिक निर्णय था। एक अन्य कारण भारतीय निर्यात को बढ़ावा देकर भारतीय रुपये को मज़बूत करने का समर्थन करना था। दिसंबर, 2022 में भारत ने पहली बार भारतीय रुपये में कच्चे तेल के आयात के लिए रूस को भुगतान किया। इससे भारतीय रुपए पर बाजार से लगातार बढ़ती दर पर डॉलर खरीदने का कुछ दबाव कम हुआ है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप दुनिया के कई देश जो भारत से आयात करने में रुचि रखते थे और डॉलर की कमी के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, अब वे अपने आयात के लिए भारतीय रुपए में भुगतान कर सकते हैं। भारतीय रुपये में व्यापार के निपटान की सुविधा के लिए अब तक भारतीय बैंकों ने यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इज़राइल, रूस और संयुक्त अरब अमीरात सहित 19 देशों के साथ 'विशेष वोस्ट्रो खाते' खोले हैं।

रूस की तरह, इन 19 देशों में से कुछ अन्य देश भारत को बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं और उन्हें उनके निर्यात के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसे देश भारत से अधिक से अधिक उत्पादों के आयात के लिए अपने भारतीय रुपये के भंडार का उपयोग करने की संभावना रखते हैं। भारत में उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा के अधीन भारत से निर्यात को पर्याप्त बढ़ावा मिल सकता है। रुपए में भुगतान से बढ़ते वैश्विक आर्थिक जोखिमों के बीच कीमती विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद मिल सकती है।

रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति में भी अनुरूप परिवर्तन किए गए हैं, भारतीय रुपये में चालान, भुगतान और निर्यात/आयात का निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11.07.2022 के अनुरूप है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार भारतीय रुपये में निर्यात लाभ के लिए निर्यात लाभ और निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए विदेश व्यापार नीति में और बदलाव किए गए हैं। ये परिवर्तन यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्यातक निर्यात प्रोत्साहन के हकदार बने रहें, भले ही उनके निर्यात का भुगतान भारतीय रुपये में वसूल किया गया हो।

31 मार्च, 2023 को घोषित विदेश व्यापार नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के माल और सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि यह लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल, कुछ

लोगों को यह भी लगता है कि देश इससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकता है। 2014 में, जब हमारा सकल घरेलू उत्पाद 2000 अरब अमेरिकी डॉलर था, तो हमारी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सिर्फ़ 452.3 अरब डॉलर था। अब, जब हमारी जीडीपी 3.4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, तो हमारा निर्यात 767 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। रुपये के व्यापार की नई पहल के साथ, जब हमारी जीडीपी 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, 2000 अरब डॉलर का निर्यात मुश्किल नहीं रहेगा।

आज भी भारत में महंगाई की दर बाकी दुनिया के मुकाबले कम है। इसके अलावा, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ग्रोथ बढ़ने का असर जीएसटी की प्राप्तियों पर भी दिख रहा है। हालांकि, आयात शुल्क जीएसटी प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा है, मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात पर मूल्यवर्धन भी जीएसटी में वृद्धि का कारण बन रहा है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में होने से रुपये में व्यापार निपटान को और बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, भारत का निर्यात प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं रहा है, फिर भी कृषि उत्पादों, रक्षा वस्तुओं और कई अन्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि प्रभावी रही है। फिर भी, सेवाओं के निर्यात में वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण रही है। 2000 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात और सामान और सेवाओं के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ असाधारण करने की जरूरत है।

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद रुपये में व्यापार निपटान को मंजूरी देने के इस ऐतिहासिक कदम के लिए सरकार को बधाई देती है और सरकार से इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने का आग्रह करती हैः

- अधिक देशों को व्यापार मुद्रा के रूप में रुपये का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करके ऐसा कर सकता है।
- व्यापार के लिए रुपये का उपयोग करना आसान बनाए जाने का प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें रुपये के बाजार में अधिक तरलता प्रदान करना और व्यवसायों के लिए रुपया खाते खोलना आसान बनाना शामिल हो सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना। इसमें विदेशी निवेशकों को भारतीय रुपए–मूल्यवर्गित संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।

उपरोक्त के अलावा, भारत रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठा सकता हैः

- एक मजबूत रुपया आधारित बांड बाजार का विकास करना। यह व्यवसायों को निवेश विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा और उनके लिए रुपये में पूंजी जुटाना आसान बना देगा।
- पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में रुपये के प्रयोग को बढ़ावा देना। इससे भारत को इन देशों के साथ व्यापार के लिए विदेशी मुद्राओं के उपयोग की आवश्यकता को कम करने में मदद मिलेगी।
- अन्य देशों के साथ रुपये–मूल्य वाले व्यापार के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित करने के लिए काम किया जाये। इससे व्यवसायों के लिए उन देशों के साथ रुपये में व्यापार करना आसान हो जाएगा, जिनका भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं है।
- पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर प्रतिबंध की नीति में इस स्तर पर कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अतीत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट में एक रक्षक साबित हुआ है।

इन कदमों को उठाकर, भारत रुपये को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्रा बनाने में मदद कर सकता है। यह डॉलर पर भारत की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके कई लाभ हो सकते हैं। इन कदमों को उठाकर भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को डॉलर के मूल्य में उतार–चढ़ाव से बचाने में मदद करेगा और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। ❑❑

सही है दो हजार के नोट की वापसी का निर्णय

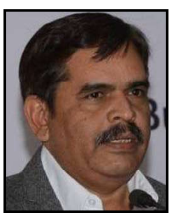

माना जा रहा है कि चूंकि 2000 का नोट आमजन के व्यवहार से लगभग बाहर हो चुका था, इसलिए आम जनता पर इन नोटों की वापसी से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ 20 हज़ार रूपये तक के 2000 के नोटों को किसी भी दिन बैंक जाकर बदलवाया जा सकता है और उसके लिए 30 सितंबर तक का समय रिजर्व बैंक ने दिया है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

नवंबर 2016 की शाम 8:00 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश के जरिए 500 रूपए और 1000 के नोटों की वैधानिक वैधता को समाप्त करने का निर्णय लोगों से साझा किया तो पूरा देश चकित हो गया था। नोटबंदी के कारण कठिनाईयों के बावजूद आम जनता का भरपूर समर्थन इस निर्णय को मिला। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बाबत जोर–शोर से विरोध किया लेकिन आम जनता ने इस नोटबंदी को कालेधन, भ्रष्टाचार, नकली करैंसी, आतंकवाद, नक्सलवाद और पत्थरबाजी के विरुद्ध एक युद्ध के हथियार के रूप में स्वीकार किया।

कुछ कठिनाइयों के बाद देश में नगदी बहाल हुई लेकिन उस समय देश में वैधानिक नगदी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रही, उसके लिए केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों के बदले में 500 और 2000 के नोटों का चलन शुरू कर दिया। गौरतलब है कि उस समय देश में कुल 17.74 लाख करोड़ रुपए की करैंसी जनता के पास थी, जिसमें से 85 प्रतिषत 500 और 1000 के नोटों के रूप में थी। 500 के नोटों के मुद्रण में देरी के कारण देश में करैंसी की कमी के कारण ज्यादा से ज्यादा 2000 के नोटों को जारी करना सरकार और रिजर्व बैंक की मजबूरी थी। गौरतलब है कि मार्च 2018 तक 2000 रूपए के नोट 6.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे।

बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के नाम पर 2000 रूपये के नोट का जारी किया जाना विमुद्रीकरण की भावना के ही विरूद्ध था। इसलिए 2000 के नोटों की वापसी मार्च 2018 से ही शुरु हो गई थी। गौरतलब है कि प्रारंभ में चलन में आए 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्च 2023 तक मात्र 3.62 लाख करोड रुपए तक ही रह गए। कहा जा सकता है कि सरकार ने 2000 के नोट जारी तो किए थे, लेकिन उसकी मंशा इन नोटों के चलन को धीरे धीरे कम करने की ही थी। रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के कुल जारी नोटों में से 89 प्रतिशत मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे, जो वैसे भी अपना समय काल पूरा कर चुके हैं। निष्कर्ष यह है कि 2000 रूपये के नोटों की वापसी कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं कहा जा सकता।

विमुद्रीकरण के बाद घटा है करैंसी का उपयोग

विपक्षी दल यह कहकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का यह दावा कि वह विमुद्रीकरण का मकसद डिजिटल भुगतानों द्वारा 'लेस कैश' यानी नगदी के कम उपयोग की अर्थव्यवस्था की और आगे बढ़ाना था, सही सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद तो नगदी की मात्रा बढ़ गई है। उनका कहना है कि विमुद्रीकरण के समय देश में कुल 17.74 लाख करोड रुपए की नगदी जनता के पास थी जो दिसंबर 2022 तकं बढ़कर 32.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन यह समझना होगा कि वर्ष 2015–16 में देश में चालू कीमतों पर जीडीपी मात्र 135 लाख करोड रुपए थी, जो 2022–23 में बढ़कर 272 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जीडीपी के अनुपात में नगदी पूर्व में 13.14 प्रतिषत से घटती हुई अब मात्र 11.91 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यानी डिजिटलीकरण का असर यह हुआ है कि देश में 'कैश' का चलन कम हो गया है।

रिजर्व बैंक का यह कहना है कि सामान्य जनता के पास 2000 के बहुत कम नोट हैं। इसका मतलब यह भी है कि 2000 के जो नोट चलन में हैं, वे अधिकतर उन लोगों के पास हैं, जिन्होंने अपने धन (या यूं कहें कि कालेधन) को नकदी के रखा हुआ है, ऐसे में रिजर्व बैंक का कहना है कि इस निर्णय से बैंकों की जमा में भारी वृद्धि हो जाएगी। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता भी।

ऐसा भी देखने में आया है कि 2000 रूपए के नोटों का उपयोग अपराधियों, आतंकवादियों और गैरकानूनी कार्यों में संलग्न लोगों द्वारा ज्यादा होता है। इन नोटों के बंद होने से कुछ हद तक इन गतिविधियों को लगाम भी लग सकेगी।

विमुद्रीकरण के बाद अर्थव्यवस्था को हुआ लाभ

हालांकि विमुद्रीकरण के विरोधियों का कहना है कि विमुद्रीकरण से छोटे उद्यमियों को नुकसान हुआ, रोजगार घटे और अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। लेकिन आंकड़ों से यह बात सिद्ध नहीं होती।2015–16 के बाद से अब तक के लगभग 6 वर्षों में चालू कीमतों पर जीडीपी 135 लाख करोड़ से बढ़ कर 272 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है, यानि दुगनी से भी ज़्यादा। अगर स्थिर कीमतों पर भी देखें तो इस बीच जीडीपी में प्रतिशत वृद्धि हुई है, जबकि इस बीच के 2 साल कोरोना से प्रभावित रहे। देश के निर्यात वर्ष 2013–14 में 465.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2022–23 तक 767 अरब डॉलर हो गए हैं। कृषि, सेवा, उद्योग सभी क्षेत्रों में प्रगति दिखाई दे रही है। सरकारी मदद से ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए आवास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन सभी इस बात की ओर इंगित करते हैं कि अर्थव्यवस्था बिना बाधाओं के आगे बढ़ रही है।

विमुद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ मुद्रा स्फीति के संदर्भ में हुआ है। गौरतलब है कि विमुद्रीकरण के बाद के 6 वर्षों (दिसंबर 2016 से नवंबर 2022 के बीच), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उपभोक्ता मुद्रास्फीति) में केवल 32.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उससे पहले के छह वर्षों (दिसंबर 2010 से नवंबर 2016 के बीच) में यह वृद्धि 54. 1 प्रतिशत थी।ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि 500 और 1000 के पुराने नोटों के चलन से बाहर होने पर देश में बड़े पैमाने पर विदेशों और खासतौर पर शत्रु देशों से आ रहे नकली नोट चलन से बाहर हो गए। चूंकि करैंसी की मात्रा ही घट गई (नकली नोटों के बाहर होने से), तो मुद्रास्फीति का कम होना स्वभाविक ही था।

सबसे खास बात तो यह रही कि पाकिस्तान जैसा शत्रु पड़ोसी देश जिसकी अर्थव्यवस्था ही भारत में नकली करैंसी भेजकर चलती थी, को अचानक एक बड़ा धक्का लगा और अभी तक उसकी अर्थव्यवस्था लगभग धवस्त हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों की बंदी के बाद पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई, उनके विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गए और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय देनदारियों में कोताही के कुचक्र में फंस गया। आज पाकिस्तान का रूपया डॉलर के मुकाबले में 295.65 रूपए प्रति डॉलर पहुंच चुका है। 2016 में 104.7 पाकिस्तानी रूपए एक डालर के मुकाबले हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी लगाम लगी है। यही नहीं नक्सलवादी गतिविधियां भी पहले से घटी है।

माना जा रहा है कि चूंकि 2000 का नोट आमजन के व्यवहार से लगभग बाहर हो चुका था, इसलिए आम जनता पर इन नोटों की वापसी से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ 20 हज़ार रूपये तक के 2000 के नोटों को किसी भी दिन जाकर बैंक से बदलवाया जा सकता है और उसके लिए 30 सितंबर तक समय रिजर्व बैंक ने दिया है। जिनके कालाधन 2000 रूपए के नोटों के रूप में पड़ा है और यदि वे बैंकों में जमा नहीं करते तो फ़ौरी तौर पर कुछ विशिष्ट प्रकार का खर्च बढ़ सकता है, उसका भी सकारात्मक लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा। यानि कहा जा सकता है कि पहले से ज्यादा पारदर्शी अर्थव्यवस्था, कालेधन पर लगाम, बैंकों की जमा में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि आदि से अर्थव्यवस्था को सकारात्मक लाभ ही होंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इससे भारत के बैंकों समेत वित्तीय संस्थानों में लगभग 1 लाख करोड़ रूपए और जुड़ जाएंगे। ❑❑

नकली नोटों से असली तबाही

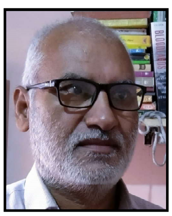

केंद्र की सरकार ने दो हजार रुपए की नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया है और इन रुपयों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इससे 2000 रूपये के बड़ी नोट के नकली संस्करण पर रोक लग जाएगा लेकिन 100, 50, 200 रूपए की छोटी नोटों की शक्ल में बड़े पैमाने पर बाजार में बांटे जा रहे नकली नोटों का क्या होगा?

– अनिल तिवारी

नकली नोट, उसका असली के रूप में इस्तेमाल, नकली नोट रखना या नकली नोट बनाने या उसका उपकरण रखने पर या नकली नोट बनाने के सामान या नकली नोट बनाने या बैंक नोट से मिलते जुलते दस्तावेज का इस्तेमाल करना, भारतीय दंड संहिता की धारा 489–अ से 489–ई तक के तहत दंडनीय अपराध है। इन मामलों में देश की अदालतें जुर्माना या सात साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास या संगीन जुर्म को देखते हुए दोनों सजाएं एक साथ दे सकती हैं।

इतने सख्त कानून के बाद भी नकली भारतीय नोट लाखों–करोड़ों की तादाद में आए दिन देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद या जब्त किए जा रहे है। वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के बाद दो हजार रुपए की नोट जारी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दावा किया था कि इसमें सुरक्षा के पर्याप्त फीचर रखे गए हैं, उनकी नकल करना काफी मुश्किल है। फिर भी ऐसा नहीं हुआ। जाली नोटों की समस्या बनी हुई है। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2016 से 2023 के बीच बाजार में नकली नोटों की संख्या करीब 10.7 प्रतिशत बढ़ गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटबंदी के बाद से अब तक जितने भी जाली नोट पकड़े गए हैं उनमें करीब 60 प्रतिशत नोट दो हजार रुपए के हैं। जाहिर है इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है जिसका कोई तय मंसूबा है। हमारी जांच एजेंसियों के पास इस बात के सबूत हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की देखरेख में इस किस्म का आर्थिक अपराध चलाया जा रहा है। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगेंद्र सिंह की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दशकों से नकली भारतीय नोट छापने तथा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स के विमानों के जरिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई के रास्ते भेजने का काम करती रही है। इसका खुलासा समय–समय पर पकड़े गए लोगों से भी होता रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आई एस आई लगभग दो हजार करोड रुपए हर साल आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए भेजती है। बहुतायत यह नकली करेंसी ही होती है।

नकली करेंसी असली करेंसी के साथ–साथ अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। इसे समझने के लिए करेंसी की भूमिका पर गौर करना होगा। करेंसी या कोई नोट अपने आप में कोई कीमत नहीं रखते। उनमें मूल्य आता है उस वादे से, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर इस कागज पर लिखता है "मैं धारक को इतने रुपए चुकाने का वचन देता हूं"। रिजर्व बैंक भी

इस करेंसी को अपनी मनमर्जी के मुताबिक नहीं छाप सकता, बल्कि उसे एक नीति के तहत छापना होता है। कोई भी केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था में नोटों की असीमित आपूर्ति नहीं कर सकता। मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य होता है कि बाजार में सेवाओं, वस्तुओं और करेंसी की सप्लाई के बीच एक अनुपात बना रहे। रिजर्व बैंक या दूसरी सरकारी एजेंसियों के हिसाब से करेंसी बहुतायत में नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली ताकतें भारी मात्रा में नकली नोट छाप कर नुकसान पहुंचाती है।

नकली करेंसी का सीधा मतलब है कालाधन। कालाधन, यानी जिसका कोई अधिकारिक हिसाब किताब अर्थव्यवस्था में नहीं है। काला धन यथासंभव गैरकानूनी और अनुत्पादक गतिविधियों में लगता है। आतंकवादी नेटवर्क में शामिल जो लोग नकली करेंसी लेते हैं वह भी इसका इस्तेमाल कानूनी गतिविधियों में नहीं करते। इसलिए नकली करेंसी का मामला सिर्फ मौद्रिक नीति के चलते चिंता का विषय नहीं है इसे लेकर चिंता सुरक्षा एजेंसियों को भी है।

जांच एजेंसियों के मुताबिक असामाजिक तत्व एवं आतंकवादी संगठनों द्वारा एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत अवैध आर्थिक सौदे संपन्न होते हैं एवं इन अवैध आर्थिक सौदों का निपटान नकली मुद्रा में ही अक्सर किया जाता है।भारत के पड़ोसी देश भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भारत में नकली मुद्रा के प्रचलन प्रसार को बढ़ावा देते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि देश में भारी मात्रा में नकली नोट बरामद और जब्त किए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच भारत में नकली नोटों की बरामदगी में 107 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। इस दौरान वर्ष 2016 में दो हजार रुपए के 2272 नकली नोट, 2017 में 74898 नकली नोट, 2018 में 54776 नकली नोट, 2019 में 90566 नकली नोट एवं 2020 में 244834 नकली नोट बरामद हुए थे।

हालांकि केंद्र की सरकार ने दो हजार रुपए की नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया है और इन रुपयों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इससे 2000 रूपये के बड़ी नोट के नकली संस्करण पर रोक लग जाएगा लेकिन 100, 50, 200 रूपए की छोटी नोटों की शक्ल में बड़े पैमाने पर बाजार में बांटे जा रहे नकली नोटों का क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 10.7 प्रतिशत नकली नोट चलन में है। इसका मतलब यह है कि करेंसी की 10 प्रतिशत रकम अर्थव्यवस्था में लगातार तबाही मचा रही है। कुल मिलाकर या गहन चिंता का विषय है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों और रिजर्व बैंक के बीच तालमेल जरूरी है। रिजर्व बैंक की ओर से हर साल इस संबंध में एक अधिकारिक आंकड़ा भी जनता के सामने आना चाहिए ताकि जनता भी अपने स्तर पर नकली नोटों के प्रति जागरूक हो सके। दो हजार रुपए की नोट को लेकर जनता में थोड़ी बहुत जागरूकता अपने आप दिखाई देती है, लेकिन छोटे नोट को लेकर जनता में सजगता के भाव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में जन जागरण अभियान चलाकर जनता को मुस्तैद कर सकता है। जहां तक नकली नोटों के चलन को रोकने के उपाय का सवाल है तो हमें बार–बार करेंसी चेंज करते रहना चाहिए। कुछ अन्य देशों में जब फर्जी नोटों का प्रचलन बढ़ा तो उन्होंने इस चुनौती का सामना नोट बदल कर ही किया था। वर्ष 2016 के बाद हमने नोटों का रंग और डिजाइन नहीं बदला है। दुनिया में आजकल नई तकनीक आ गई है। नई तकनीक के उपयोग से ऐसे नोट छापे जा रहे हैं, जिनका प्रतिरूप बनाना मुश्किल है। यदि बनाया भी गया तो वह तुरंत पकड़ में आ जाता है। सवाल है कि हम नई तकनीक का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। आखिर नकली नोट का मसला सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही नहीं अपराध और आतंकवाद से जुड़ा मसला भी है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून

आहार, आरोग्य और अर्थतंत्र

अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। गैर–पारम्परिक खाद्य पदार्थों के सेवन से कई क्रानिक और अनुवांशिकीय अर्थात चिरस्थाई एवं वंशानुगत चलते रहने वाले रोग भी उत्पन्न होने लगे हैं। कई खाद्य पदार्थों में विद्यमान म्यूटाजेन अर्थात 'उत्परिवर्तक रसायन मानव डी.एन.ए. तक को प्रभावित कर अनुवांशिकी एवं सामाजिक मनोविज्ञान तक में परिवर्तन ला रहे हैं। आयुर्वेद में व्यक्तिगत प्रकृति परीक्षण आधारित और ऋतु आधारित आहार का वैज्ञानिक विधान रहा है। दूसरी ओर 'डी.एन.ए. वाइज टेस्ट' जैसे परीक्षणों से व्यक्ति के डी.एन.ए. विविध आहार एवं उनके यौगिक, किस व्यक्ति के अनुकूल तथा किसके प्रतिकूल सिद्ध होंगे, यह जानना भी संभव है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, नमक और अन्य पदार्थ किसके शरीर की कार्य प्रणाली को कैसे प्रभावित करेंगे, यह पता लगाया जा सकता है। आयुर्वेद में भी अनादिकाल से व्यक्तिगत प्रकृति परीक्षण आधारित एवं ऋतु आधारित आहार का वैज्ञानिक विधान भी रहा है। इस प्रकार आहार विज्ञान जन–स्वास्थ्य सुधार का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है।

आहार और रोग–भार

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आहार में सब्जियों एवं फलों के अभाव मात्र से असमय मरने वालों की संख्या ही 2.7 लाख है। वैश्विक आकलनों के अनुसार 19 प्रतिशत जठरांत्रपरक कैंसर, 31 प्रतिशत धमनी काठिन्य जनित हृदय रोग और 11 प्रतिशत पक्षाघात जनित मृत्यु की रोकथाम सम्भव है। आजकल खाद्य पदार्थों में पाये जाने वाले म्यूटाजेन अर्थात उत्परिवर्तक जो व्यक्ति के डी.एन.ए. को प्रभावित कर उसमें वंशानुगत विकृतियों तथा रोग उत्पन्न कर देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आहार शास्त्र के माध्यम से जनस्वास्थ्य में सुधार लाया जाना महत्वपूर्ण है।

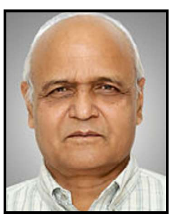

पुनः आवश्यकता है कि हमारे आहार में हम पारम्परिक तिलहन आधारित तेलों को स्थान दें। इससे किसान पुनः तिलहन की खेती से लाभान्वित होंगे और तेल के उत्पादन एवं व्यापार का रोजगार प्रधान विकेन्द्रित तंत्र विकसित होगा।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

दो दशक पूर्व सरसों के तेल में 80 प्रतिशत तक ताड़ के तेल (पॉम–ऑइल) की ब्लेण्डिंग की अनुमति देने से देश में सरसों के तेल में आयातित पाम ऑयल की मिलावट का मार्ग खुल गया था। कई उत्पादकों द्वारा सरसों के तेल में 80 प्रतिशत तक पामोलीन का तेल मिलाकर बेचा जा रहा था। इससे देश में तिलहन उत्पादन से किसान हतोत्साहित होने लगे और आज देश को 70 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करने पड़ते हैं।

आहार, आनुवांशिकी, रोग एवं सामाजिक मनोविज्ञान

प्राचीन आयुर्वेदिक निघण्टु विज्ञान में प्रत्येक खाद्य पदार्थ के गुणधर्म, परिपाक, प्रकृति आदि पर सटीक, सूत्रबद्ध एवं विस्तृत जानकारी मिलती है। खाद्य तेलों पर ही विचार करें तो पारम्परिक तेलों यथा तिल, सरसों, मूंगफली आदि के गुणधर्म वर्णन में तेल के संबंध में उसे केशवर्द्धक, मेघावर्द्धक वृद्धावस्था रोकने वाला श्रेष्ठ रसायन तेल कहा है। आधुनिक अनुसंधानों में तिल के ऐसे सभी गुणों की पुष्टि होती है। ऐसे ही प्रत्येक पारम्परिक तेल और प्रत्येक खाद्य पदार्थ के विस्तृत के गुणधर्म मिलते हैं। आजकल देश में पारम्परिक तेलों के स्थान पर औद्योगिक तेलों, जो बड़े उद्योगों में उत्पादित होते हैं यथा पामोलीन, सोयाबीन आदि का चलन बढ़ रहा है। कुल तेलों में 50 प्रतिशत पामोलीन या ताड़ के तेल, 25 प्रतिशत सोयाबीन के तेल व शेष 25 प्रतिशत पारम्परिक सरसों, मूंगफली व तिल के तेलों का प्रयोग हो रहा है। पामोलीन अर्थात ताड़ का तेल जिसका बड़ी मात्रा में आयात भी हो रहा है, कई रोगों का जनक माना जा रहा है। एक पौष्टिक एवं उत्तम तेल होते हुए भी, पामोलीन तेल को उबालने पर इसमें **'ग्लाइसिडिल फेट्टी एसिड एस्टर्स'** उत्पन्न हो जाते हैं। ये एस्टर कैंसर के जनक और हृदय, यकृत एवं गुर्दों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते हैं। यह तेल रक्त का थक्का जमने से रोकने वाली औषधियों को भी प्रभावित करता है।

इसी प्रकार सोयाबीन तेल पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 2015 से हुए अनुसंधानों के अनुसार यह लगभग 100 वंशाणुओं अर्थात जीन्स को अवरूद्ध कर देता है। वह आक्सीटोसिन हारमोन उत्पादक वंशाणु या जीन को भी अवरूद्ध कर देता है। आक्सीटोसीन हार्मोन को स्नेह और प्रेम का हार्मोन माना जाता है जिसके कारण रक्त में इसकी मात्रा माता–पिता एवं बच्चों के बीच स्नेह की प्रगाढ़ता और व्यक्ति के सामाजिक समूहों में सहजता प्रदान करता है और सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। कैलिफोर्नियां विश्वविद्यालय के अध्ययनों में सोयाबीन तेल को मस्तिष्क में अनुवांशिकीय विघटन अर्थात जेनेटिक डीजनरेशन का कारण भी माना है। सोयाबीन से तेल निकालने बाद बचने वाली खली अर्थात सोयामील उसके बने सोया मिल्क एवं उसके अन्य उत्पादों या बिस्किट व टोफु आदि में सोयाबीन तेल के ये दुर्गुण बिल्कुल नहीं होते हैं। यूरोप व अमेरिका में तेल के स्थान पर इन्हीं का उपयोग होता है।

तेल एवं अर्थतंत्र

पारम्परिक तिलहनों (तिल, मूंगफली व सरसों आदि) को उगाने पर किसानों को अच्छा लाभ मिलता था और गांवों में ही एक लाख से अधिक कोल्हू रोजगार का साधन बनते थे। सोयाबीन एवं पामोलीन आदि औद्योगिक तेल है, जिन्हें करोड़ों के निवेश वाले कारखानों में उत्पादित किया जाता है अथवा आयात किया जाता है। आज इन तिलहनों के तैल के स्थान पर औद्योगिक तेलों का उपभोग तीन चौथाई हो गया है। पारम्परिक तिलहनों के तेल का उपयोग मात्र एक चौथाई रह गया है।

दो दशक पूर्व सरसों के तेल में 80 प्रतिशत तक ताड़ के तेल (पॉम–ऑइल) की ब्लेण्डिंग की अनुमति देने से देश में सरसों के तेल में आयातित पाम ऑयल की मिलावट का मार्ग खुल गया था। कई उत्पादकों द्वारा सरसों के तेल में 80 प्रतिशत तक पामोलीन का तेल मिलाकर बेचा जा रहा था। इससे देश में तिलहन उत्पादन से किसान हतोत्साहित होने लगे और आज देश को 70 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करने पड़ते हैं। अब दो वर्ष पूर्व वर्तमान सरकार ने 8 जून 2021 से सरसों के तेल में पामोलीन या चावल की भूसी के तेल की 80 प्रतिशत तक मिलावट की इस छूट को प्रतिबन्धित कर दिया था। इस रोक से जनस्वास्थ्य का संरक्षण होगा और किसान पुनः तिलहन की खेती की ओर अग्रसर होंगे और छोटे रोजगार प्रधान कोल्हू उद्योग पुनः पनपेगा।

खाद्य तेल उद्योग, जन स्वास्थ्य और वैश्विक परिदृष्य

पामोलीन सबसे अल्प मूल्य का तेल होने से इसका उपयोग साबुन उत्पादन एवं वनस्पति घी यथा डालडा आदि में होता था। इसके सस्ता होने से सर्वाधिक खाद्य पदार्थ उत्पादक आजकल रिफाइण्ड पामोलीन का उपयोग करते हैं। इसीलिए देश में कुल

तेलों में पामोलीन का उपभोग 50 प्रतिशत हो गया है। आज हर चौथे कुटुम्ब में कोई कैंसर रोगी दिखलाई दे जाता है। पामोलीन अब तक दक्षिण पूर्व एशिया से आयात होता रहा है। अब देश में भी ऑइल पॉम की खेती बढ़ने से पॉम या ताड़ का जंगल खड़ा होने पर हम उसी तेल पर आश्रित हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू के काल में पॉम तेल को हाइड्रोजनीकृत कर जब वनस्पति घी अर्थात डालडा का विपणन प्रारम्भ किया, तब डालडा का देश भर में विरोध होने पर सरकार को इस पर जनमत संग्रह कराना पड़ा था।

भारत में 1990 के दशक में इन औद्योगिक तेलों के प्रवेश का भी विदेशी कम्पनियों का ही कुचक्र रहा है। जब 1998 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पॉम ऑइल व औद्योगिक तेल सड़ रहे थे। तब पूरे देश में राजस्थान से बंगाल तक सरसों के तेल में पीले धतूरे अर्थात सत्यानाशी की मिलावट कराकर ड्राप्सी की बीमारी का आतंक पैदा करने का षड़यन्त्र किया था। सरसों के पकने व पीले धतूरे के बीजों का समय सर्वथा अलग–अलग है। देश में इस खरपतवार पीले धतूरे के बीज इतनी मात्रा में पैदा भी नहीं होते हैं कि सरसों के बीजों में इतने बड़े पैमाने पर मिलावट की जा सके। यह मिलावट विदेशी बाजार शक्तियों ने कराई। तब देश भर में सरसों के तेल को नष्ट करना पड़ा और तात्कालिक मांग पूर्ति हेतु पॉम तेल व सोयाबीन जैसे औद्योगिक तेलों का आयात करने पर उन विदेशी कम्पनियों को देश में बाजार मिल गया। तब देश सभी प्रकार के तेल की खुली बिक्री पर रोक लगानी पड़ी। इससे देश भर में कई हजार कोल्हू बन्द हुए और तिलहन की खेती से किसान दूर जाने लगे। इसके बाद तो हमारे खाद्य तेलों में पारम्परिक तिलहन आधारित तेलों के स्थान पर पॉम व सोयाबीन के औद्योगिक तेलों ने स्थान ले लिया। यूरोप और अमेरिका में टोफू एवं सोया बिस्किट तथा पशु आहार हेतु बहुत बड़ी मात्रा में सोयाबीन के प्रसंस्करण में तेल अनुपयोगी बाई–प्रोडक्ट होता है। इसकी खपत भारत जैसे बड़े खाद्य तेल उपभोगकर्त्ता देश में ही सम्भव है। स्वाधीनता के बाद कई दशकों तक भारत खाद्य तेल निर्यायक देश था। आज हमें अपने उपभोग का 70 प्रतिशत तेल आयात करना पड़ता है। पुनः आवश्यकता है कि हमारे आहार में हम पारम्परिक तिलहन आधारित तेलों को स्थान दें। इससे किसान पुनः तिलहन की खेती से लाभान्वित होंगे और तेल के उत्पादन एवं व्यापार का रोजगार प्रधान विकेन्द्रित तंत्र विकसित होगा।

डी.एन.ए. परीक्षण आधारित आहार का महत्व

किन्हीं दो व्यक्यिों की अनुवांशिकी कभी समान नहीं होती है। इसलिए कई बार एक ही आहार सामग्री दो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर परस्पर विरोधी परिणाम देती हैं। यह व्यक्ति की विशेष जीन संरचना के कारण हो सकता है। डी.एन.ए. परीक्षण द्वारा अनुकूल खाद्य पदार्थों का निर्धारण सम्भव है। इस हेतु मुंह के लार (सेलाईवा) का "डी.एन.ए. वाइज टेस्ट" कराया जा सकता है। विविध अनुवांशिकीय विशेषताओं वाले भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के वजन शरीर की कार्यकी एवं अंगों की कार्य प्रणाली पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और फाइबर जैसे मेक्रो न्युट्रिएण्ट्स के प्रति प्रतिक्रिया, नमक के प्रति व्यक्ति सापेक्ष रक्तचाप की संवेदनशीलता विटामिन और सूक्ष्मपोषी तत्वों के प्रति अस्थि खनिज घनत्व (बी.एम.डी.) शरीर–भार सूचकांक (बाड़ी मा इण्डेक्स) की संवेदनशीलता, जैसी सभी जानकारियाँ व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत शारीरिक व अनुवांशिकीय विशिष्टताओं के अनुरूप आहार निर्धारण में सहायता करता है।

भारतीय आहार रोगों के शमन में प्रभावी

आजकल कई अनुसंधानों में भारतीय आहार रोग प्रतिरोधक सिद्ध हो रहे हैं। इन अनुसंधानों के अनुसार केवल डीएनए में गड़बड़ी से आनुवांशिकीय बीमारियां नहीं होती है। सही आहार बीमारी पर भी रोक लगा सकता है। जर्मनी ल्यूबेक यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार भारतीय आहार से आनुवांशिक बीमारियां नहीं होती हैं। तीन वैज्ञानिकों रूस के डॉ. अर्तेम वोरोवयेव, इजराइल की डॉ. तान्या शेजिन और भारत के डॉ. यास्का गुप्ता के अनुसंधान के अनुसार, पश्चिमी आहार व्यक्तियों में आनुवांशिक रोगों को बढ़ाने का काम करता है जबकि, भारतीय न्यून कैलोरी आहार ऐसे रोगों से बचाता है। ल्यूपस नाम के रोग से ग्रसित चूहों जिसका सीधा संबंध डीएनए से होता है और इसमें शरीर के अंग जैसे किडनी, दिल, फेफड़े, ब्लड सेल्स, मस्तिष्क और कई अंग नष्ट हो जाते हैं। समूह को फास्टफूड का सेवन कराया और दूसरे समूह को भारत का शाकाहारी आहार – स्टार्च, सामान्य तेल में बने हल्दी युक्त दाल चावल, सब्जी खिलाये। पहले समूह में ल्यूपस बढ़ गया और भारतीय आहार वाला समूह ल्यूपस से मुक्त होने लगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार खाद्य पदार्थ हमारे जन स्वास्थ्य, रोग भार, चिकित्सा तंत्र के आर्थिक प्रभार एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि की पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं। आज खाद्य जनित रोगों व उनके अनुवांशिकी प्रभावों के आलोक में न्युट्री–जीनोमिक्स एवं न्यूट्रीजेनेटिक्स जैसी स्वास्थ्य विज्ञान की शाखाओं पर अध्ययन बढ़ाने का भी आधार प्रदान करते हैं। ❑❑

'यमुना कालिंग' भविष्य की आवाज

यमुना किनारे 4 जून 2023 को आयोजित यमुना संसद मुहिम दिल्ली में खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। हो भी क्यों न! लगभग एक सदी के पश्चात नदी के लिए कोई शहर एक साथ जागृत हुआ है। भागती दौड़ती कंक्रीट का जंगल बनती दिल्ली में हजारों जागृत लोगों ने सुस्त दिल्ली को झंझोरने का प्रयास किया है। दिल्ली के यमुना किनारे 22 किलोमीटर के दायरे में 8 बिंदुओं पर सहस्त्रोंबाहू मानव श्रंखला बनी। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक संगठन, स्कूली छात्र, व्यापारी वर्ग सब एक दूसरे का हाथ थामें... मां यमुना के आंचल में जा पहुंचे। नम आंखों से यमुना मैया ने अपने पुत्र – पुत्रियों का अभिनंदन किया... इंद्रदेव भी बरसे और नदी का बहाव भी पिछले दो दिनों में सरकारों ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की... वजीराबाद बैराज में नियमित मात्रा से ज्यादा पानी छोड़ा गया... इसे इस मुहिम या जन आंदोलन का दबाव मान सकते हैं। सरकारे अपना काम अपनी गति से करेगी परंतु यमुना संसद के माध्यम से दिल्ली की जनता का मां यमुना के प्रति भाव जागृत हुआ। आने वाली पीढ़ियों को कैसी जलराशि सौंप कर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे. .. यह विमर्श यमुना संसद के माध्यम से दिल्ली और देश भर में शुरू हो चुका है ।

साथियों, सनातन धर्म में सदैव नदियों को माता के समान पूजनीय और वंदनीय बताया गया है। महाभारत महाकाव्य के रचियता महर्षि वेदव्यास ने 'मां' के बारे में लिखा है–

नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः।
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रपा।।

अर्थात, माता के समान कोई छाया नही, कोई आश्रय नही, कोई सुरक्षा नही। माता के समान इस दुनिया मे कोई आश्रयदाता नही। कदाचित् यही कारण है कि माता को हिंदू धर्म में देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। किंतु यह अथाह दुख का विषय यह है कि जीवनदायिनी मां यमुना, जिसकी महिमा वेदों पुराणों में भी वर्णित है, आज स्वयं अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। यमुना, यमी, कालिंदी और असित, इसके हर नाम के पीछे एक कथा है। यमुना नदी का उल्लेख प्राचीन ऋग्वेद, अथर्ववेद, स्कंद पुराण, पद्म पुराण सहित अनेक प्राचीन ग्रँथों में मिलता है।

दिल्ली के सैकड़ों छोटे नाले और 38 बड़े नालों का पानी यमुना में गिरता है। इस पानी को साफ करने के लिए सभी नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना था, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसा नहीं हुआ है।

–राजकुमार भाटिया

सूर्य की पुत्री तथा यम की बहन, ये कालिंदी पर्वत पर अवतरण लेने के कारण कालिंदी कहलाई। इसी के किनारे बैठ कर आदि शंकराचार्य जी ने "यमुनाष्टक" स्तोत्र की रचना थी तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में दिल्ली का आज का निगम बोध घाट कभी प्रसिद्ध "जातस्मर" तीर्थ हुआ करता था। इसी के किनारे को भगवान कृष्ण ने श्रेष्ठ स्थान माना और पांडवों ने उनके आदेश पर यहीं इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था। वही जीवनदायिनी यमुना जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा, इंद्रप्रस्थ बनने से लेकर अनेक राजवँशों और फिर मुगलकाल से लेकर 1911 में फिर से ब्रिटिश राज में देश की राजधानी तक पूरे इतिहास की साक्षी रही है। अंग्रेजों ने भी स्थान के सौंदर्य से वशीभूत होकर यहां पर वॉइस राय भवन स्थापित किया जो आज राष्ट्रपति भवन के नाम से भारत के गणतंत्र की शान है। दिल्ली बसने से लेकर आज तक यह यमुना ही है जो इस शहर की प्यास बुझाती आई है, जिसके

घाट इस शहर की जीवनरेखा हुआ करते थे। आज वही यमुना तिल–तिल कर मर रही है, दम तोड़ रही है। वर्तमान में तो स्थिति ऐसी हो गयी है कि जब हम इसे एक गंदे नाले के रूप में बहते देखते हैं तो इसे नदी कहने में भी हर दिल्लीवासी को लज्जा अनुभव होती होगी। देश की राजधानी दिल्ली से बहने वाली इकलौती नदी, जो राजधानी की शान भी हो सकती थी आज अपने दुर्भाग्य पर रो रही है और चीख – चीख कर पूरे विश्व को बता रही है कि देखो इस शहर की जीवनदायिनी, ममतामयी यमुना की दुर्दशा को देखो। देश–विदेश के सैलानी जब दिल्ली घूमने आते होंगे तो यमुना की दशा देख कर हमारे विषय में क्या धारणा उनके मन मे बनती होगी ? यह प्रश्न विचारणीय है ।

महान भक्त कवि सूरदास जी जिनका जन्म भी यमुना किनारे ही हुआ था उन्होंने भगवान कृष्ण के विरह में तड़फती यमुना पर एक दोहा लिखा था –– देखियती कालिंदी अति कारी। अहो पथिक कहियों उन हरि सौं, भई बिरह जुर जारी। अर्थात भगवान कृष्ण के ब्रजभूमि को छोड़ देने से यमुना उनके विरह के ज्वर से बुरी तरह तप रही है और पीड़ा और कष्ट से उसका रँग काला पड़ गया है। द्वापर में कृष्ण के वियोग में यमुना काली पड़ गयी थी पर वर्तमान युग मे इसे गंदा काला नाला बना देने का जिम्मेदार कौन है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

दिल्ली के सैकड़ों छोटे नाले और 38 बड़े नालों का पानी यमुना में गिरता है। इस पानी को साफ करने के लिए सभी नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना था, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसा नहीं हुआ है। राज्य सरकार के यमुना एजेंडे की पोटली चुनाव के आस–पास ही खुलती है। यही वजह है कि सभी नालों का प्रदूषित पानी यमुना नदी में गिरकर उसे जहरीला बना रहा है। लगभग 224 किमी. की दूरी स्वछंद रूप से तय करने के बाद नदी पल्ला गांव के निकट दिल्ली में प्रवेश करती है और वजीराबाद में एक बार फिर से बैराज के माध्यम से घेर ली जाती है। यह बैराज दिल्ली के लिए पेयजल आपूर्ति करता है। इसके बाद नदी में अनौपचारिक या अंशतः उपचारित घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल नदी में मिलता है। एक बार फिर लगभग 25 किमी. बहने के बाद ओखला बैराज के आगे इसके पानी को आगरा नहर में सिंचाई के लिए डाल दिया जाता है। आखिर में यमुना में अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों का पानी मिलता है और लगभग 1370 किमी. चलने के बाद यह इलाहाबाद में गंगा और भूमिगत सरस्वती से मिलती है।

जीवनदायिनी यमुना जल भरकर पर्वतों से मैदान तक का दुर्गम सफर तय करके क्या इसीलिए अपने बच्चों के पास आती है कि उनका भरण पोषण करने के बदले में वही बच्चे अपनी मां को रोग ग्रस्त कर दें? इस सृजना को विर्सजन का साधन बनाकर उसका नीर ही सुखा दें। वास्तव में हमने अपनी इस पूजनीय की स्थिति एक वृद्ध आश्रम में छोड़ी हुई मां के समान दयनीय बना दी है। धर्म एक सत्य है जो अलग–अलग ऐतिहासिक निष्ठाओं का साक्षात्कार करवाता है। द्वापर हो या कलयुग, युधिष्ठिर जैसा धर्म का हस्ताक्षर हो, या आप और हम जैसे साधारण मानव। धर्म की दृष्टि में सब समान हैं। अपने भाइयों की खोज में सरोवर तट पर पहुंचे युधिष्ठिर से बगुला रूप में प्रकट हुए यक्ष ने प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर पूर्ण निष्ठा, धर्म परायणता और धैर्य से देने के उपरांत ही उनके भाइयों को प्राण दान मिल सका। युगों के अंतराल ने जिस प्रकार हमारी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का पतन किया है, वह सर्वविदित है। इस घटना को चाहे लाखों वर्ष बीत चुके हैं, किंतु, आज भी मनुष्य की सुप्त आत्मा को चैतन्य करने और शुद्ध और बुद्ध से पुनः परिचय कराने के लिये यक्ष को प्रकट होना ही पड़ता है।

हमारी यही दीन हीन माता यमुना आज अपनी आखिरी सांस गिनती हुई हमसे पूछ रही हैः

यमुनाः यमुना भवान् कः अस्ति? (यमुना आपकी कौन है)?

दिल्लीवासीः मेरी माँ (मम् मातुः)

यमुनाः यमुनाम् मलिनं कः अकरोत् (यमुना को मैला किसने किया)।

दिल्लीवासीः निरूतर

यमुनाः मातुः अनादरे कः अकरोत् (मां का तिरस्कार क्यों किया)

दिल्लीवासीः निरूतर

यमुनाः मातुः श्वसनं कः अवरुद्ध अकरोत् (माँ की सांस किसने रोकी)

दिल्लीवासीः निरूतर

यमुनाः श्रीरम् इच्छेत् तर्हि सन्वारान एताणान् प्रश्नानाम् उत्तरे यच्छ। (पानी चाहिये तो इन प्रश्नों के उत्तर दो)

दल्लीवासीः निरूतर

आज दिल्ली के पास इन यक्ष प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। दिल्ली अपनी मां का सम्मान करने में पस्त हो चुकी है। इस शहर का प्रत्येक निवासी जीवनदायनी माता यमुना का अपराधी है। हे मां! आपके किंकर्तव्यविमूढ़ बालक अपने अपराधों की आपसे करबद्ध क्षमा याचना यमुना संसद के माध्यम से कर रहे हैं।

शास्त्र की मान्यतानुसार यमुना की स्वच्छता सेवा करने वालों से यमुना पिता सूर्य प्रसन्न रहते हैं और उन्हें रोगमुक्त रखते हैं। यमुना के भाई शनि और यम भी अपनी बहन की सेवा करने वालों को अपनी दोष छाया से परे रखते हैं। तब तक के लिए ‘जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी। ❑❑

(राजकुमार भाटिया दिल्ली में राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में स्थापित नाम है। देश बार में उनके द्वारा स्थापित रोटी बैंक का अनुकरण करते अनेक फूड बैंक चल रहे है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजकुमार भाटिया सामाजिक विषयों पर निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रस्तुतिकरण करते है। यमुना संसद के मूल सूत्रधारो में से एक है।)

मोदी सरकार के नौ साल

काम अधिक, बातें कम

मोदी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने की दहलीज पर जा पहुंची है। सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बरक्स विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे है। अन्य विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का हिसाब 'सावन के अंधे को सूझत है हरो–हरो' की तर्ज पर 9 सालों को 365 से गुणा कर फिर 9 से भाग देते हुए मुहावरे की भाषा में 9 दिन चले अढ़ाई कोस का जुमला–उछाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि 2014 के बाद से मोदी शासन की उपलब्धियां मध्य सुबह की धूप की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत एनडीए की सरकार ने 2014 से एक लंबा सफर तय किया है। इन 9 सालों में राजनीति के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी मंदी की चपेट में है ठीक उसी समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली है।इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने शासन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विश्व मंच पर एक सम्मानजनक स्थान अर्जित करने से लेकर एक स्थिर और बढ़ती अर्थव्यवस्था होने तक। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पहले की सरकारों ने भी देश को आगे ले जाने का प्रयास किया लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि पहले की सरकारें भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति में व्यस्त थी उन्होंने देश को बदलने पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था।

वर्ष 2014 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2 ट्रिलियन अमेरिकी डालर था आज यह 3.73 ट्रिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय 1574 अमेरिकी डालर से बढ़कर 2601 अमेरिकी डालर हो गई है। इसे भारतीय रुपए के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2013–14 के 104.73 लाख करोड़ से बढ़कर 2022 23 मई 272.04 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। इन आंकड़ों से मुद्रास्फीति में वृद्धि को हटा दें तो वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के दौरान हमारी वार्षिक जीडीपी वृद्धि 5.6 प्रतिशत रही है। निश्चित रूप से यह एक आश्वस्त करने वाली उपलब्धि है खासकर जब हम करोना जैसी महामारी से दो–चार हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है वह दिन दूर नहीं जब भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा और प्रत्येक भारतीय के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा।

– के.के. श्रीवास्तव

जीडीपी के लिहाज से भारत 2014 में दुनिया में दसवें स्थान पर था आज पांचवें स्थान पर कब्जा कर लिया है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, भारत से आगे है। वास्तव में तुलना के और अधिक उपयुक्त आधार का उपयोग करते हुए देखा जाए तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध अमेरिका और चीन के बाद भारत सबसे अधिक बढ़ता हुआ देश बन गया है।

कोविड–19 की काली छाया दुनिया के सभी देशों पर सीधे पड़ी लेकिन भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जिसकी विश्व स्तर पर सराहना हुई। सराहना करने वालों में डब्ल्यूएचओ भी शामिल रहा। महामारी के दौरान दुनिया के समक्ष पूरी आबादी को टीकाकरण करने, भोजन, दवा और अन्य आजीविका की जरूरतों की व्यवस्था करने के मामले में भी चुनौतियां पेश की। इसके अलावा बंद हो रहे व्यवसाय को फिर से व्यवस्थित करके अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर वापस लाने का कठिन कार्य भी बना

रहा। ऐसे भयावह दौर में भारत में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण के साथ 80 करोड लोगों को 2 साल से अधिक समय तक मुफ्त अनाज देकर मदद कीए जिसके चलते भारत दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी टीकाकरण के मोर्चे पर असफल रहे किंतु भारत ने योग्यतम टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अंत्योदय के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय किया है। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों का ध्यान करते हुए सरकार ने शौचालय घरों का निर्माण और चिकित्सा बीमा का प्रावधान किया है। ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय के तहत मनरेगा के बजटीय आवंटन में लगातार वृद्धि करते हुए पिछले 9 सालों में 5.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में औसत जीवन प्रत्याशा भारतीय के लिए 70 वर्ष से अधिक थी। पीएम आवास योजना के तहत 4.1 घर करोड़ घरों जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.85 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.23 करोड़ को सरकारी सहायता से घर बनाने की मंजूरी दी गई है। इसमें 2.87 करोड़ घर पिछलेले 8 वर्षों से भी कम समय में बनाए जा चुके हैं।

मोदी काल में भारत की विकास गाथा का प्रकाश स्तंभ बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश है। यह सामाजिक ऊपरी पूंजी अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक विकास की नीव प्रदान करती है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के पहले देश में प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता था वही अब प्रतिदिन लगभग 23 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही है। यूपीए शासन के दौरान सड़क निर्माण पर केंद्र सरकार द्वारा 10000 करोड़ वार्षिक खर्च किया जाता था एनडीए सरकार ने इसे बढ़ाकर 15000 करोड़ तक कर दिया है। मोदी सरकार में न केवल सड़कें, रेलवे, जलमार्ग और हवाई मार्ग के काम में भी सराहनीय वृद्धि देखी गई है, पिछले 9 सालों में भारतीय रेलवे ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही, सधी हुई नीति और समर्पण के कारण ही संभव हो पाया है। इन 9 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 148 यानी दोगुनी हो गई है। मोदी सरकार की गति शक्ति योजना को दुनिया भर में सराहना मिल रही है।इस योजना को बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों के समन्वित विकास को सुविधाजनक बनाने के अलावा सबसे कुशल तरीके से निवेश के लिए भी मुफीद माना जा रहा है।

स्वस्थ भारत सुखी भारत को आगे करते हुए मोदी सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए भारी निवेश का फैसला किया है। 10 करोड गरीब परिवारों को इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की सुविधा दी गई है। खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालयों का निर्माण, धुआं रहित रसोईघर के लिए उज्जवला के तहत गैस सिलेंडर की उपलब्धता, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण, एलईडी बल्ब, हरित ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सरकार ने महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है।

समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का सीधा लाभ प्राप्त करने के लिए 45 करोड़ जीरो बैलेंस खाता खोला गया है। इससे वित्तीय समावेशन, भ्रष्टाचार में कमी, सब्सिडी का सही लक्ष्यीकरण और सार्वजनिक धन का कुशल उपयोग होने लगा है।सभी तक आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए जन धन बैंक खाता और आधार मोबाइल से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था से आम आदमी की पहुंच बड़ी है। कांग्रेस के राज में कहा जाता था कि केंद्र द्वारा 1 रूपये भेजा जाता है तो लाभार्थी को 15 पैसा पहुंचता है, मोदी सरकार में इस पर अंकुश लगा है। अब केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है।

मोदी के नेतृत्व में दुनिया के देशों के बीच भारत की साख बढ़ी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो तवज्जो मिल रहा है, वर्ष 2014 के पहले ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री की हालिया जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की यात्राओं से भी यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि भारत एक महत्वाकांक्षी देश के रूप में देखा जा रहा है तथा दुनिया के पैमाने पर तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरना चाहता है। यह सहज ही संभव है क्योंकि भारत जी20 के सम्मेलनों का आयोजन कर दुनिया को यह संदेश देने में सफल रहा है।

हालांकि इस दौरान केंद्र की सरकार को भूमि अधिग्रहण, कृषि कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम विमुद्रीकरण जैसे मुद्दों पर व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार ने अपने फैसलों से न सिर्फ देश दुनिया के लोगों को चौंकाया है बल्कि भारत को एक अति विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में गुणात्मक प्रगति की है। विरोधी दल भले आलोचना करें लेकिन देश का आम आदमी मोदी के नेक इरादों को महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा और प्रत्येक भारतीय के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। ❑❑

नयी दिल्ली से टकराव की नित नयी जमीन तैयार करता बीजिंग

कश्मीर में जी 20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक का चीन द्वारा खुला बहिष्कार यह समझने के लिए काफी है कि बीजिंग भारत के साथ संबंध सुधारने के प्रति गंभीर नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बकायदा एक बयान जारी कर कहा कि "उनका देश कश्मीर जैसे किसी विवादित क्षेत्र में जी20 बैठक के आयोजन का दृढ़ता से विरोध करता है और ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होगा।" बावजूद इसके भारत ने श्रीनगर में जी 20 देशों की सफल बैठक का आयोजन कर चीन को इसका ठीक जवाब दे दिया।

यही नहीं मार्च के अंतिम सप्ताह में अरूणाचल प्रदेश के इटानगर में हुई जी 20 की एक अन्य बैठक का भी चीन ने बायकॉट किया, जबकि इस बैठक में 100 से ज्यादा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसी समय भारत को उकसाने के लिए बीजिंग ने अरुणाचल के कई गांवो, नदियों का चीनी भाषा में नया नामकरण भी कर दिया। चीन के भारत के प्रति आक्रामक रवैये को देखकर इस बात की आशंका हो रही है कि बीजिंग एक नए टकराव की जमीन तैयार कर रहा है।

देखा जाए तो कश्मीर को विवादित बताकर जी 20 बैठक से अलग होने की चीन की घोषणा भारत के मामले में सीधा हस्तक्षेप है। चीन अभी तक इसे विवादित मुद्दा बताकर यूएनओ के करार के मुताबिक हल करने की सिफ़ारिश करता रहा है। ऐसा वह पाकिस्तान के प्रति अपने प्यार के इजहार में करता है। पर पहली बार अपने को आगे रखकर कश्मीर को मुद्दा बनाया और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। यह चीन की दोहरी नीति का सबूत है। एक तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी एससीओ की बैठक में यह कह कर गए कि सीमा विवाद को एक तरफ परे रखकर भारत को व्यापार एवं अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ वह स्वयं व्यापार बढाने की संभावनाओं को कुचलने का प्रयास करता है। क्या बीजिंग को यह मालूम नहीं है कि कश्मीर में जी 20 देशों के सदस्यों के बीच पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने पर ही चर्चा हो रही है, जिसे बिगाड़ने

भारतीय सेना के कमांडर सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति को संभालने के लिए पूरी क्षमता से डटे हुए हैं। चीन यदि कूटनीति के बजाय आक्रामकता की नीति पर कायम रहता है तो आने वाले दिनों में फिर से किसी बड़े टकराव की आशंका बनी रहती है।

– विक्रम उपाध्याय

की वह असफल कोशिश कर चुका है।

हालांकि चीन के साथ तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया ने भी कश्मीर में हुई मीटिंग से दूरी बनाई, लेकिन किसी ने भी वह बयान नहीं दिया, जो पाकिस्तान दिलाना चाहता था। पाकिस्तान जी 20 का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद वह सदस्य मुस्लिम देशों को जम्मू–कश्मीर न जाने के लिए मनाने में जुटा रहा। इस्लामाबाद ने कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन, राजनीतिक उत्पीड़न और अवैध गिरफ्तारियों की मनगढंत किस्सों को बेचने की कोशिश की। किसी और देश ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन चीन ने इस्लामाबाद की हां में हां मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

भारत के पास इस समय जी 20 देशों की अध्यक्षता है और उसे पूरा अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र में बैठकों का आयोजन कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के सदस्य देशों ने भारत की संप्रभुता का पूरा सम्मान किया और खुशी खुशी कश्मीर में आकर शिरकत की। 22 से 24 मई के बीच चले इस आयोजन में भारत ने जिन 25 देशों को आमंत्रित किया था, उनमें से 20 देशों ने भाग लिया। चीन इससे ही समझ सकता है कि विश्व मंच पर भारत के समकक्ष उसकी हैसियत क्या है।

चीन ने कश्मीर मामले पर तब भी भारत का इतना खुला विरोध नहीं किया था जब भारत ने 2019 में जम्मू–कश्मीर से धारा 370 हटाकर दो संघ शासित क्षेत्रों, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख का गठन कर दिया था। जबकि लद्दाख भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ बसा है और चीन ने इसके कुछ हिस्सों को भी विवादित घोषित कर रखा है।

इधर भारत और चीन के बीच एक सैन्य गतिरोध अभी भी बना हुआ है।

> **चीन के रवैये से भारत सरकार और राजनयिकों को निराशा ही मिली है। पिछले 23 अप्रैल को 18वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद भी विवाद हल करने की दिशा में कोई सकारात्मक पक्ष सामने नहीं आया। चीन ने इन बैठकों को सकारात्मक तो बताया है लेकिन साथ में यह सलाह भी दी है कि अमेरिका की शह पर भारत चीन के खिलाफ आक्रामक रुख न अपनाये।**

डोकलाम की घटना को हुए छह साल और तवांग नदी पर हुए खूनी संघर्ष के तीन साल होने वाले हैं, लेकिन अब भी सीमा विवाद के समाधान के कोई संकेत नहीं हैं। जबकि मंत्री और सैन्य कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमेशा ही तनाव बना रहता है।

चीन एक तरफ बातचीत का माहौल बनाने का दावा करता है और दूसरी तरफ लगातार एकतरफा कार्रवाई कर संबंधों में जटिलता बनाए रखता है। पिछले महीने चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम चीनी भाषा में बदल दिया। चीन इन्हें अपना क्षेत्र दक्षिणी तिब्बत कहता है। जबकि भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया था। भारत से लगी अपनी सीमाओं पर चीन तेजी से सैन्य और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। भारत भी उसी त्वरित गति से सुरंगों, सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है।

हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर पूर्वोत्तर में लगभग 3000 सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए 57 अरब डॉलर की परियोजनाओं का अनावरण कर चीन को माकूल जवाब दिया था। शाह ने चीन को जवाब देते हुए कहा था – हमारी नीति स्पष्ट है कि हम सभी से शांति चाहते हैं। कोई भी हमारी एक इंच जमीन का भी अतिक्रमण नहीं कर पाएगा।

चीन के रवैये से भारत सरकार और राजनयिकों को निराशा ही मिली है। पिछले 23 अप्रैल को 18वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद भी विवाद हल करने की दिशा में कोई सकारात्मक पक्ष सामने नहीं आया। चीन ने इन बैठकों को सकारात्मक तो बताया है लेकिन साथ में यह सलाह भी दी है कि अमेरिका की शह पर भारत चीन के खिलाफ आक्रामक रुख न अपनाये। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि चीन की तरफ से अनिश्चितता बनी हुई है और भारत अपनी सीमा की रक्षा के लिए तत्पर है। राजनाथ सिंह ने यहां तक कह दिया कि सीमा प्रबंधन समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों को खत्म कर दिया है, और संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति पर आधारित है।

भारत लगातार कह रहा है कि चीन द्वारा सीमा पर सेना के भारी जमावड़े से द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं बन पाएंगे। संबंध तभी सुधर सकता है जब पीएलए अलग हो जाए और अतिरिक्त बल वापस ले ले। सीमा पर इस समय दोनों ओर लगभग एक एक लाख सेना के जवान तैनात हैं। भारतीय सेना के कमांडर सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति को संभालने के लिए पूरी क्षमता से डटे हुए हैं। चीन यदि कूटनीति के बजाय आक्रामकता की नीति पर कायम रहता है तो आने वाले दिनों में फिर से किसी बड़े टकराव की आशंका बनी रहती है। ❑❑

https://hindi.oneindia.com/opinion/china-boycott-g20-summit-in-jammu-kashmir-to-create-tussle-with-india-775756.html

स्वास्थ्य के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण

बीते दिनों केंद्रीय आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य उन बीमारियों पर अनुसंधान करना है जो राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बीमारी बनी हुई है वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़कर स्वास्थ्य व्यवस्था को समग्र और एकीकृत बनाना है।

– डॉ. जया कक्कड

एकीकृत चिकित्सा एलोपैथी के साथ–साथ पारंपरिक दवाओं के तरीकों को भी मुख्यधारा में लाकर चिकित्सा में मौजूद समस्याओं का वैज्ञानिक निदान करना चाहती है। इसका उद्देश्य सिर्फ बीमारी के लक्षणों को खत्म करना ही नहीं बल्कि गहराई से बीमारियों पर अध्ययन करना है, ताकि आधुनिक चिकित्सा पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। कई एक अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि चिकित्सा की प्राचीन प्रणालियां कई रोगों से निपटने के लिए जरूरी है। इसलिए हमें एलोपैथी उपचार को पूर्णतया वैकल्पिक नहीं मानना चाहिए। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां चिकित्सा में पारंपरिक प्रणालियों पर झुकाव ज्यादा है। जैसे एम्स के डॉक्टरों ने योग की उपयोगिता को स्वीकारा है तो वही डॉक्टर नरेश त्रेहन धमनियों को ठीक करने के लिए जड़ी–बूटी की सलाह देते हैं। बावजूद एलोपैथिक चिकित्सक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और वैकल्पिक दवाओं की वैज्ञानिकता पर लगातार संदेह करते रहे हैं। लेकिन खारा सच यह भी है कि वैकल्पिक चिकित्सा समय की कसौटी पर खरी उतरी है। एलोपैथी के रोगियों ने भी कोरोना महामारी के दौरान इस बात को खुले मन से स्वीकार किया है।

बीते दिनों केंद्रीय आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य उन बीमारियों पर अनुसंधान करना है जो राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बीमारी बनी हुई है वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़कर स्वास्थ्य व्यवस्था को समग्र और एकीकृत बनाना है।

भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूती के साथ विकसित किया जाए तथा साथ ही साथ आयुष (जोकि संक्षिप्त रूप है आयुर्वेद, यूनानी, सिंधिया, होम्योपैथी) के तहत बीमारियों और इलाज को लेकर वैज्ञानिक मांगों के स्तर पर परीक्षण करते हुए क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। निश्चित रूप से अगर इसके लिए कोई तंत्र विकसित होता है तो आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपनी पहचान सिद्ध करने का अवसर भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि एलोपैथिक पद्धति

बहुत सारी बीमारियों का निदान करने में असफल है। जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, किडनी की विफलता। आज एलोपैथी दवाएं सिर्फ अल्पकाल के लिए ही प्रभावी होती है। इसके साथ ही यह लंबे समय के लिए शरीर के लिए हानिकारक है साथ ही जो व्यक्ति एलोपैथी दवाओं का आदी है उसमें एक से अधिक बीमारियां देखी जा सकती हैं। वही ऐसे लोगों की भी तादाद बढ़ी है जो बीमारियों के इलाज में एक से अधिक प्रकार के उपचारों का संयोजन करते रहते हैं।

इन तथ्यों को देखते हुए यह वांछनीय और अनिवार्य है कि दवाओं को एकीकृत करने के क्षेत्र में और अधिक वैज्ञानिक शोध की जरूरत है।नियामक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैज्ञानिक परीक्षण पक्षपात मुक्त और किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रभाव उत्पादकता और जोखिमों के बारे में किसी भी दिशा में गलत सूचना न दी जाए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दवा की कोई भी खुराक जादू की गोली नहीं होती।

इस बीच खबर है कि आयुष तकनीकी सलाहकार बोर्ड, जो केंद्र सरकार की तकनीकी सलाहकार बोर्ड है, ने पारंपरिक दवाओं के अनुचित विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए इस नियम पर गंभीरता से काम कर रहा था। यहां गौरतलब यह है कि सरकार ने सलाहकार बोर्ड को पुनर्विचार का आदेश आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन तब विपणन करने वाली कुछ दवा कंपनियों द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में जारी किया है। याचिका दायर करने वालों में कुछ ऐसी दवा कंपनियां भी हैं जो लंबे समय से विभिन्न आरोपों का सामना कर रही हैं। रक्तचाप पर अंकुश लगाना, गतिमान हृदय की रुकावटें या तीसरे चौथे स्टेज के कैंसर के इलाज आदि को लेकर दवा कंपनियों के दावों को लेकर भी आरोप–प्रत्यारोप इन कंपनियों के ऊपर लगते रहे। कोविड–19 के दौरान भी वैकल्पिक दवाओं की उपचारात्मक शक्तियों के बारे में केंद्रीय रूप से अप्रमाणित दावे किए गए। नियम 170 सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। वर्ष 2018 से 21 के बीच नकली दवा बनाने के लिए एक कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था, वही आयुष दवाओं के लिए आपत्तिजनक विज्ञापन को लेकर 18812 मामले दर्ज किए गए थे। वास्तविक मामले इससे कहीं अधिक हो सकते हैं। नियम 170 के ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूट 1945 का हिस्सा होने के कारण इसमें कई खामियां हैं। यह नियम केवल आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर ही रोक लगाता है। आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में कुछ नहीं कहता, इसलिए अधिनियम को और मजबूत करने की भी आवश्यकता है, ताकि यह वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच में खरा उतर सके इसलिए इसे और अधिक शक्ति प्रदान करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के अति उत्साह में केंद्र सरकार इस नियम को और अधिक कमजोर करने पर आमादा नजर आ रही है।

प्रभावी नियामक तंत्र के अभाव में बहुत हद तक वे अपने काम में सफल भी होते रहे हैं लेकिन केंद्र की सरकार ने वैकल्पिक प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक सूस्पष्ट नीति तैयार की है।

इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि इसरो प्रमुख ने हाल ही में कहा है कि विज्ञान के सिद्धांतों की उत्पत्ति वेदों से हुई थी और बाद में उन्हें पश्चिमी खोजों के रूप में फिर से परिभाषित किया गया था। हालांकि इस पर भी उंगली उठाने वाले यह कह सकते हैं कि उनके दावे का वैज्ञानिक आधार क्या था?

तकनीकी रूप से रोज–रोज आगे बढ़ रही आज की दुनिया में सही प्रकार के नियामक निरीक्षण की आवश्यकता है। ऐसे में जबकि एलोपैथिक दवाएं कठोर परीक्षणों के दौर से गुजरती हैं वैकल्पिक दवा एक ऐसी वैज्ञानिक जांच से अक्सर बच जाती है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 में एक मसौदा संशोधन आया था जो आयुर्वेद उत्पादों के विज्ञापनों की छानबीन करता है। देखा गया कि कोविंड महामारी के दौरान यहां अपना काम करने के लिए रास्ता ही भटक गया। सभी वैकल्पिक दवाएं पाखंड है, का तर्क देने वाले दरअसल नीम हकीम के सिस्टम को बदनाम कर अपनी उंगली सीधा करना चाहते हैं। प्रभावी नियामक तंत्र के अभाव में बहुत हद तक वे अपने काम में सफल भी होते रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने वैकल्पिक प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक सुस्पष्ट नीति तैयार की है। 'पहुंच और सामर्थ्य' को आधार मानते हुए सरकार ने वैज्ञानिक स्वीकार्यता और जवाबदेही को आगे कर वैकल्पिक दवाओं के साथ–साथ सभी प्रणालियों को एकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एकीकृत प्रणाली के लिए मजबूत वैज्ञानिक परीक्षण और दूसरी ओर एक प्रभावी रूप से लागू किए गए मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता है। कोविड19 के दौरान आधुनिक चिकित्सा की कुछ कमियां उभरकर सामने आई। बहुत हद तक वैकल्पिक दवाओं के माध्यम से लोगों को राहत मिली लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस कारण अवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का लाइसेंस दे दिया गया हो।❑❑

देश के विकास एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है समान नागरिक संहिता

भारत के विधि आयोग ने सामान्य जनता एवं मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से एक माह के भीतर समान नागरिक संहिता के बारे में विचार आमंत्रित किये है। भारत के संविधान में लिखित समान नागरिक संहिता (यूसीसी–यूनिफार्म सिविल कोड़)को लागू करने के लिए गुजरात व उत्तराखंड़ राज्यों की सरकारों ने एक कमेटी गठित की है जिनकी रिपोर्ट आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के विधान सभा के चुनावों के लिए जारी किये अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया था। परन्तु हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गई तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने हिमाचल प्रदेश भाजपा के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का उल्लेख होने पर यह कहा कि कि कांग्रेस भी इस समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। परन्तु सरकार को इस विषय पर आम सहमति बना लेनी चाहिए न कि इस विषय पर राजनीति की जाय। कांग्रेस को यह तो समझ में आ ही गया है कि वह समान नागरिक संहिता के मामले में नकारात्मक रवैया अपना कर घाटे में रहेगी जैसा कि उसने शाहबानों और तीन तलाक के मामले में अपनाया था। अतः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं खड़गे को समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी बात सार्वजनिक रुप में जोरदार तरीके से रखनी चाहिए।

समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता वह विचार है जिसे लागू करने का समय आ गया है क्योंकि यह संविधान सम्मत है तथा 26 जनवरी 1950 से ही संविधान में उल्लिखित है। देश के सभी भारतीयों पर एक विषय में एक कानून लागू किया जाय। समान नागरिक संहिता में होने वाले कानून से विवाह, विरासत, उत्तराधिकार, दत्तक, तलाक, जमीन व मकान की संपत्ति के मालिकाना हक, दहेज, वक्फ, अभिभावक अधिकार, भेंट, दान से जुड़े कानूनों और धर्म, जाति, सम्प्रदाय तथा संस्कृति के भेदभाव से देश की जनता को मुक्ति मिल सकेगी। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो देश के प्रत्येक समुदाय चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो अथवा बौद्ध हो, पर समान रुप से लागू होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, पंथ अथवा क्षेत्र का हो सब के लिए सिविल कानून एक ही होगा परन्तु संविधान में इसकी स्वीकृति के उपरान्त भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकी है।

अब गुजरात एवं उत्तराखंड़ को समान नागरिक संहिता पर शीघ्र से शीघ्र कोई प्रारुप जनता के सामने लाकर उस पर बहस शुरु करवानी चाहिए। परन्तु यह भी अच्छा होता कि भाजपा भाासित राज्यों में यह प्रक्रिया शुरु हो जाती न कि सिर्फ चुनावों के आगमन पर ही समान नागरिक संहिता का मुद्दा गर्माता है और सबसे उपयुक्त तो यह होता कि केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए क्योंकि समान नागरिक संहिता सम्पूर्ण देश की आवश्यकता बन गई हैं। समान नागरिक संहिता इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो गई है कि विवाह, संबंध विच्छेद, उत्तराधिकार आदि व्यक्तिगत मामलों के मुकदमों की संख्या न्यायालयों में गम्भीर स्थिति में पंहुच गई है। इन मुकदमों की संख्या तथा न्यायालयों पर बोझ तभी कम हो सकता है जबकि देश में केन्द्र सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाय। गैर भाजपा भाासित राज्यों को भी भारतियों की भलाई के लिए समान नागरिक संहिता को लागू

समान नागरिक संहिता मात्र हिन्दुओं के लिए ही आवश्यकत नहीं है। इसका महत्व देश की दूसरे प्रमुख समुदाय मुसलमानों के लिए भी महत्वपूर्ण है परन्तु मुसलमानों को इस मुद्दे पर राजनीति करके भड़काया जा रहा है जो देश की एकता एवं अखंड़ता के लिए अनुकूल नहीं है।

– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

करने की पहल करनी चाहिए।

जबकि दंड़ के प्रावधान जो आई पी सी में है वह सब समुदायों के लिए समान है। उसके लिए अपराधी का ध र्म, मजहब, जाति, आदि नहीं देखी जाती है। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंड़ा रहा है। परन्तु मात्र चुनाव के समय ही इस पर चर्चा होती रही है। कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कहा है कि ऐसा कानून बनाने का अधिकार मात्र संसद को है। समान नागरिक संहिता में होने वाले कानून से विवाह, विरासत, उत्तराधिकार, दत्तक, तलाक, जमीन व मकान की संपत्ति के मालिकाना हक, दहेज, वक्फ, अभिभावक अधिकार, भेंट, दान से जुड़े कानूनों और धर्म, जाति, सम्प्रदाय व संस्कृति के भेदभाव से देश की जनता को मुक्ति मिल सकेगी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड़ में समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए समिति बन चुकी है उनकी रिपोर्ट आना बाकी है।

समान नागरिक संहिता मात्र हिन्दुओं के लिए ही आवश्यकत नहीं है। इसका महत्व देश की दूसरे प्रमुख समुदाय मुसलमानों के लिए भी महत्वपूर्ण है परन्तु मुसलमानों को इस मुद्दे पर राजनीति करके भड़काया जा रहा है जो देश की एकता एवं अखंड़ता के लिए अनुकूल नहीं है। परन्तु अब कुछ मुस्लिम धर्मिक एवं सामाजिक संगठन समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपने विचार प्रगट करने लगे है। उनके अनुसार देश के विकास तथा सभी देशवासियों के हित में एक समान कानून समय की जरुरत है। इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले मुस्लिम संगठनों से भी समाज को बचना चाहिए तथा इन पर नकेल कसने की पैरोकारी होनी चाहिए। मौलाना सुहैब काजमी (अध्यक्ष, जमात उलेमा–ए–हिन्द) ने कहा है कि अमेरिका, कनाड़ा एवं जापान जैसे कई अन्य देशों में एक देश व एक कानून है। वहां का मुस्लिम समाज भी उसी कानून से बंधा हुआ है। भारत का मुस्लिम भी समान अधिकार चाहता है। होश तो कट्टरपंथियों को आना चाहिए जिन्होंने तीन तलाक कानून का भी विरोध किया था। ड़ॉ उमैर अहमद इलियासी (चीफ इमाम, आल इंड़िया इमाम आर्गनाइजेशन) का कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है ऐसे में हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र हित में सोचे। मुस्लिम समाज का भी समान नागरिक संहिता के मामले को भी गंभीरता से लेना चाहिए। ड़ॉ एम जे खान (अध्यक्ष, इंड़ियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड़ रिफार्म्स (इम्पार)) ने कहा कि अपना भारत देश सांस्कृतिक व ध ार्मिक विविधता वाला देश है। अगर किसी कानून से देश का विकास बाधि ात होता है तो उसमें जरुर बदलाव लाया जाना चाहिए लेकिन इसमें विविध ाता का भी सम्मान होना चाहिए। इससे एक अच्छा समाज विकसित होगा। फिरोज बख्त अहमद (शिक्षाविद्) के अनुसार मुस्लिम, ईसाई व बौद्ध के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। इससे हिन्दुस्तान बंट रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड़ जैसे संगठन इसके चलते समानान्तर सरकारें चला रहे है और धर्म के नाम पर बहका रहे है। एक समान कानून होना जरुरी है। उपर्युक्त ये चारों मुस्लिम बुद्धिजिवियों के विचार प्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक जागरण के अक्टूबर 31, 2022 के अंक में प्रकाशित हुए थे।

विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) समान नागरिक संहिता के पक्ष में सदैव ही रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में प्रतीत हो रहे है। इसका तात्पर्य है कि वे उन भ्रांतियों से मुक्त हो रहे है, जो समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा पैदा की गई थी। इन भ्रांतियों को उत्पन्न करने में देश के कुछ कथित बुद्धिजीवियों ने भी अपना योगदान दिया है।उनकी ओर से यह वातावरण पैदा किया गया है कि मुस्लिम समुदाय जो भारत में लगभग 35 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला दूसरा प्रमुख समाज है, के लिए समान नागरिक संहिता ठीक नहीं है। यह निराधार तथा भारारतपूर्ण है क्योंकि यह समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के लिए होगी, वे चाहे जिस भी पंथ, जाति व क्षेत्र के हों।

गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में पुर्तगाली भाासकों ने समान नागरिक संहिता लागू की थी। भारत में गोवा के विषय में कभी कोई समाचार नहीं प्रकाशित हुआ कि समान नागरिक संहिता से किसी पंथ विशेष के मानने वाले को कोई परेशानी हुई है।

अतः देश में समान नागरिक संहिता के बारे में भ्रान्ति न फैले, इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को इस संहिता का कोई मसौदा प्रस्तुत करना चाहिए। मसौदे पर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श होने पर ही इसमें उत्पन्न होने वाले अंदेशों व संदेहों को स्वतः ही दूर किये जा सकेंगे। समान नागरिक संहिता नागरिक अधिकारों तथा महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का काम करेगा। देश के लोगों के बीच यह भी संदेश जायेगा कि कानून की दृष्टि में सब भारतीय एक समान है। समान नागरिक संहिता लागू करने पर सरकार की नीयत पर भी सवाल नहीं उठता है। देश के विकास एवं एकता के लिए भी अब यह आवश्यक हो गया है। इसको मात्र राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाये। समान नागरिक संहिता को चुनावी मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

सुलग रहा मणिपुर

प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण पूरब का स्विट्जरलैंड कहलाने वाले मणिपुर का इतिहास ईसा पूर्व से ही काफी समृद्ध रहा है। मणिपुर को देश की 'ऑर्किड बास्केट' भी कहा जाता है। यहां ऑर्किड फूलों की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पड़ोसी राज्यों द्वारा मणिपुर को अलग–अलग नामों से पुकारा जाता था। बर्मियों द्वारा कथे, असमियों द्वारा मोगली और मिक्ली आदि नामों से पुकारा जाता था। मणिपुर को मैत्रबाक, पोंथोक्लम आदि नामों से भी जाना जाता था। पौराणिक कथाओं से भी मणिपुर का संबंध जोड़ा जाता है।

1949 में भारत का हिस्सा बना – मणिपुर के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ई. में राजा पाखंगबा से शुरू होता है। 1819 से 1825 तक यहां बर्मी लोगों ने शासन किया। 24 अप्रैल, 1891 के खोंगजोम युद्ध के बाद मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा तब मणिपुर का शासन महाराज बोधचन्द्र संभाल रहे थे। 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बन गया।

1972 में मिला पूर्ण राज्य का दर्जा मिला – 21 जनवरी, 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई।

पूर्वोत्तर में मणिपुर में हिंसा और उपद्रव बहुत चिंता के विषय हैं। राज्य के 8 जिले हिंसा की आग में जल रहे हैं। सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण यह राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर प्रश्न है। मणिपुर में जातीय हिंसा का पुराना इतिहास है परंतु मई और जून 2023 की हिंसा ने पूरे देश को उद्वेलित और आंदोलित किया है। सीमा पार म्यांमार से ईसाई कुकी आदिवासी उपद्रवियों द्वारा हिन्दू मेतेई समुदाय पर हिंसक हमले विघटनकारी गतिविधियों को प्रमाणित करते हैं। पहले भी हिंसा होती थी परंतु यह केवल पूर्वोत्तर की राजनीति तक सीमित थी और इसके स्थायी समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए।

इसके मूल में मणिपुर का एक कानून है, जिसके अनुसार सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही पहाड़ी इलाकों में बस सकते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 89 फीसदी

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच के लिए डीआईजी रैंक के अधिकारी के तहत विशेष कमिटी का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा से जुड़े छह मामले को सीबीआई जांच के लिए कार्मिक प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेज दिया है।

–विनोद जौहरी

हिस्सा पहाड़ी है। जबकि आदिवासियों से ज्यादा जनसंख्ख्या यहां पर मैतेई समुदाय की है, जिसे अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। मैतेई समुदाय की जनसंख्या राज्य में 53 प्रतिशत है, जबकि जबकि 40 फीसदी आबादी नगा और कुकी आदिवासियों की है। राज्य में 7 फीसदी समुदाय अन्य समुदाय से आते हैं। मणिपुर के इस कानून के मुताबिक 40 फीसदी नगा और कुकी आदिवासियों को राज्य के 89 फीसदी हिस्से पर बसने का अधिकार है। अनुसूचित जाति में होने के कारण मैतेई समुदाय इस अधिकार से वंचित है। वह चाहता है कि उसे भी जमीन पर बसने और जीविकोपार्जन का अधिकार मिलना चाहिए। यही कारण है कि मैतेई समुदाय खुद के लिए एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। ऑल मेइतेई काउंसिल के सदस्य चंद मीतेई पोशंगबाम ने मीडिया को बताया कि एसटी दर्जे के विरोध की आड़ में उन्होंने (कुकी ने) मौके का फायदा उठाया, उनकी मुख्य समस्या निष्कासन अभियान है। ये अभियान पूरे मणिपुर में चलाया जा रहा है लेकिन इसका विरोध सिर्फ कुकी ही कर रहे हैं।

मणिपुर के 10 प्रतिशत भूभाग पर ग़ैर–जनजाति मैतेई समुदाय का दबदबा है और यहां की कुल आबादी में से मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी 64 फ़ीसदी से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक इसी समुदाय से हैं जबकि दावा किया गया है कि 90 प्रतिशत पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में प्रदेश की 35 फ़ीसदी मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं लेकिन इन जनजातियों से केवल 20 विधायक ही विधानसभा पहुँचते हैं यह भी सत्य है कि मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिन्दू है और बाक़ी मुस्लिम लेकिन कहा जाता है।

22,347 वर्ग कि.मी में फैला पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर दो महीनों से भीषण हिंसा की चपेट में है। आगजनी, पथराव और झड़प के कारण यहां अभी तक 10 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और 85 से अधिक मौतें हो चुकी है। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। लेकिन इस सख्त आदेश के बाद भी राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू, सेना के जवानों की मुस्तैदी के बाद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे।

क्यों जल रहा मणिपुर –

1. शिड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर यानी ज्क्ब्ड 2012 से मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग करता आया है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने ये बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था।

2. मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए विचार करने की मांग की। अदालत की इसी मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर आदिवासी एकता मार्च निकला और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई और इसने लगभग पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। अनुसूचित जनजाति मांग समिति मणिपुर 10 साल से राज्य सरकार से आरक्षण की मांग कर रहा है। तीन मई को मणिपुर हाई कोर्ट का आदेश दिया कि सरकार 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर–जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। मणिपुर में ताजा हिंसा के पीछे इसी हाई कोर्ट का एक आदेश है। इस फैसले के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी।

3. पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। अभी की हिंसा चुराचांदपुर पहाड़ी जिलों में अधिक देखी गई। यहां पर कुकी और नागा ईसाई हैं। मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय लगभग 53 फीसद हैं। मणिपुर के भूमि क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं लोगों के पास है। कुकी जातीय समुह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है।

4. कुकी जातीय समूह में कई जनजातियाँ हैं। कुकी जनजातियां वर्तमान में राज्य की कुल आबादी का 30 प्रतिशत हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर मैती समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो वे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे। कुकी जनजातियों का मानना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे।

5. ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन के अनुसार अगर मेतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलता है तो वे सारी जमीन ले लेंगे। दूसरी ओर मैतेई जाति के लोगों का ये कहना है कि एसटी दर्जे का विरोध सिर्फ एक दिखावा है। कुकी आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियां बना कर अवैध कब्जा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह की दिल्ली यात्रा चिन–कुकी–मिज़ो–ज़ोमी गुट के 10 आदिवासी विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र के अलग प्रशासन की मांग के बाद हुई है, जो हाल ही में हुई झड़पों के मद्देनजर हुआ था, जिसमें 85 से अधिक लोग मारे गए थे। इन 10 विधायकों में से सात भाजपा के हैं, दो कुकी पीपुल्स अलायंस (केपीए) के हैं और एक निर्दलीय है। बाद के तीन विधायक राज्य में एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। 2022 के राज्य चुनावों से पहले, सरकार द्वारा निर्वाचित होने पर कुकी मुद्दे को हल करने का वादा करने के बाद कुकी समूहों ने भाजपा

का समर्थन किया था। मणिपुर के लगभग 30 कुकी विद्रोही समूहों में से 25 एसओओ समझौते के तहत 22 अगस्त, 2008 को उग्रवाद का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।

पुलिस के सूत्रों के अनुसार चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में मार्च के दौरान हथियार लिए हुए लोगों की एक भीड़ ने कथित तौर पर मेइती समुदाय के लोगों पर हमला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भी हमले हुए, जिसके कारण पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। सेना और असम राइफल्स ने चुराचांदपुर और इंफाल घाटी के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और काक्चिंग जिले के सुगनु में भी फ्लैग मार्च किया गया। इसके साथ ही तोरबंग में तीन घंटे से अधिक समय तक हुई हिंसा में कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ के साथ ही आगजनी की गई। आदिवासी बहुल इंफाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरिबाम और विष्णुपुर जिलों तथा आदिवासी बहुल चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब तक सैकड़ों लोग अपने घरों को खो चुके हैं और उन्हें मणिपुर या दिल्ली, दीमापुर और गुवाहाटी में राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार (2 जून) को एक बयान जारी कर कहा था कि इस समय 272 राहत शिविरों में कुल 37,450 लोग हैं। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से आगजनी के 4,014 मामले सामने आये हैं। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच के लिए डीआईजी रैंक के अधिकारी के तहत विशेष कमिटी का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा से जुड़े छह मामले को सीबीआई जांच के लिए कार्मिक प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेज दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और शीर्ष अधिकारियों के साथ मणिपुर में स्थिति की समीक्षा की। यहां तक कि केंद्र ने वहां शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल और दंगा रोधी वाहनों को भेजा। सूत्रों ने कहा कि लगभग 1,000 और केंद्रीय अर्धसैनिक बल दंगा रोधी वाहनों के साथ शुक्रवार को मणिपुर पहुंचे। श्री अमित शाह ने इसी के साथ एलान किया कि मणिपुर सरकार डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी। भारत सरकार को 2024 के लोक सभा चुनाव से पहले मणिपुर की समस्या का स्थायी समाधान निकालना होगा। ❑❑

विनोद जौहरी, पूर्व अपर आयकर आयुक्त, दिल्ली

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http:// swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

वित्तीय समावेशन से भारत में गरीब वर्ग का हो रहा कायाकल्प

15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' की घोषणा की थी और बिना समय गवाएं 28 अगस्त 2014 से यह योजना पूरे देश में प्रारम्भ कर दी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय ने देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की दशा एवं दिशा बदल दी है। इस योजना का दूसरा संस्करण अधिक लाभों को जोड़ते हुए वर्ष 2018 में प्रारम्भ किया गया था। इस दूसरे संस्करण में प्रत्येक परिवार के स्थान पर प्रत्येक उस व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की घोषणा की गई थी जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। इस पहल का नतीजा आज हम सभी के सामने है कि देश आर्थिक विकास के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया भारत को वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर एक चमकता हुआ सितारा मान रही है।

आज नागरिकों को बैंक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार आसानी से सम्पन्न किए जा रहें हैं। कुल मिलाकर भारत में बैंकिंग क्षेत्र में अतुलनीय परिवर्तन आया है, जिससे देश में वित्तीय समावेशन भी बहुत आसान बन पड़ा है।

– प्रहलाद सबनानी

किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के नागरिकों के वित्तीय सेवाओं से जुड़े होने पर भी निर्भर करता है। जितनी अधिक जनसंख्या वित्तीय सेवाओं से जुड़ी होगी, उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन, आजादी के बाद से भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा भाग और समाज का निम्न आय वर्ग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहा है। जबकि गरीबी को कम करने में वित्तीय समावेशन एक प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। वर्ष 2014 में देश के करोड़ों नागरिकों के पास मोबाइल फोन तो था परंतु उनका बैंक में बचत खाता नहीं था। नागरिक बैंक में जाने से डरते थे। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जिससे सभी नागरिक इससे होने वाले लाभ अर्जित कर सकें एवं भारत के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अतः नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। इससे हाल के दिनों में सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में एवं विशेष रूप से बैंकिंग सेवाओं में बहुत ही तेज गति से प्रगति हुई है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से आम नागरिकों के बैंकों में बचत खाते खोले गए, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, धन के प्रेषण की सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज मिलता है, हालांकि बचत खाते में कोई न्यूनतम राशि रखना आवश्यक नहीं है। एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से दो लाख रुपए का जीवन बीमा उस लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर मिलता है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले लाभ के अंतरण की सुविधा भी इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होती है।

भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर गरीब नागरिक को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबतम व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ

मिला है। आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशत नागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैकों से नहीं जुड़े थे। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक 48.65 करोड़ बचत खाते विभिन्न बैकों में खोले जा चुके हैं। साथ ही, इन खाताधारकों द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन जमा खातों में जमा की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में नागरिकों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 15.99 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 49 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा केवल 436 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 33.78 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 48 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमीयम पर उपलब्ध कराया जाता है। अटल पेंशन योजना से 5.20 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 40.83 करोड़ नागरिकों को ऋण प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना अपने प्रारम्भिक समय से ही वित्तीय समावेशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। इस योजना के प्रारम्भ के बाद, एक सप्ताह के अंदर बैंक में खोले गए खातों की संख्या को उपलब्धि के रूप में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया था। बैकों की मदद से शून्य बैलेन्स के साथ करोड़ों नागरिकों के बचत खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं। इन बचत खातों में से लगभग 67 प्रतिशत बचत खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी केंद्रों पर खोले गए हैं, जिसे मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खोले गए बचत खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया है। यह रूपे कार्ड उपयोगकर्ता द्वारा समस्त एटीएम, पोस टर्मिनल एवं ई-कामर्स वेबसाइट पर लेनदेन करने की दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2016 में 15.78 करोड़ बचत खाताधारकों को रूपे कार्ड प्रदान किया गया था एवं अप्रेल 2023 तक यह संख्या बचकर 33.5 करोड़ तक पहुंच गई है।

वर्तमान में देश में बैंकिंग सेवाएं सुगम बनाने के उद्देश्य से 6.55 लाख बैंकिंग मित्र भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उक्त योजनाओं से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार बैकिंग सेवाओं को नागरिकों के द्वार तक पहुंचा दिया गया है। वित्तीय समावेशन के लिए गांव से लेकर शहर तक गरीब से लेकर मध्यम आय के परिवार के कम से कम एक सदस्य को बैंकिंग सेवा से जोड़ने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे बहुत बड़ी हद्द तक पिछले 8 साल के दौरान प्राप्त कर लिया गया है।

गरीबी कम करने के लिए वित्तीय समावेशन एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने के बाद से देश में गरीब वर्ग के बीच बैंकिंग सेवाओं में तेजी से प्रगति हुई है। वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन का प्रमुख चालक भी बन गया है। पिछले 8 वर्षो के दौरान बचत खातों की संख्या तीन गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है कि देश का कोई भी व्यक्ति वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं से वंचित ना रहे, इसी उद्देश्य से इस योजना को प्रारम्भ किया गया था। वित्तीय समावेशन से वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ता है। साथ ही, वित्तीय समावेशन से देश में पूंजी निर्माण की दर में भी वृद्धि होती है।

वित्तीय समावेशन के माध्यम से देश के प्रत्येक परिवार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को इस लायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह देश की आर्थिक प्रगति में अपने योगदान को सार्थक कर सके। परिवार के कुछ सदस्य नहीं बल्कि परिवार के समस्त सदस्य गरीबी रेखा से बाहर आ जाएं। देश का पूरा समाज एवं समस्त प्रदेश ही आर्थिक रूप से विकसित बन जाएं। देश के समस्त समाजों को बगैर किसी भेदभाव के आगे बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय समावेशन ने आज देश के आर्थिक परिदृश्य को पूरे तौर पर बदल दिया है। यूपीआई के माध्यम से आज ऑनलाइन पैसे का तुरंत भुगतान सम्भव हो सका है एवं अब पैसे बैंक में जमा किए जाते हैं तो वह भी ब्याज के रूप में आय अर्जित करते हैं। पहिले, यह रकम घर पर पड़ी रहती थी एवं अनुत्पादक आस्ति बनी रहती थी।

आज वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, दुनिया के कई देश, भारत को मिसाल के तौर पर देखने लगे हैं कि किस प्रकार 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश ने बैंकों से उन नागरिकों को भी जोड़ा है जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे। जब तक समावेशी विकास नहीं होगा, तब तक देश का आर्थिक विकास भी गति नहीं पकड़ सकता है। पहिले लोग जहां बैंकों में जाने से डरते थे, वहीं अब उन्हें बैंकिंग सुविधाएं बैंक मित्रों के माध्यम से घर बैठे ही पहुंचाई जा रही है। आज नागरिकों को बैंक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार आसानी से सम्पन्न किए जा रहें हैं। कुल मिलाकर भारत में बैंकिंग क्षेत्र में अतुलनीय परिवर्तन आया है, जिससे देश में वित्तीय समावेशन भी बहुत आसान बन पड़ा है। ❑❑

प्रहलाद सबनानी, सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर।

राष्ट्रीय परिषद बैठक

पुणे, महाराष्ट्र (3–4 जून, 2023)

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद का आयोजन दिनांक 3–4 जून 2023 को स्त्री शिक्षण संस्थान कर्वे नगर, पुणे स्थित सीएनबीसी सभागार में हुआ। अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय सह–संयोजक – डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा, श्री अरुण ओझा, डॉ. धनपत राम अग्रवाल, डॉ. अश्वनी महाजन एवं श्री अजय पत्की ने भारत माता, राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी, पं. दीनदयाल उपाध्याय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर बैठक का शुभारंभ किया। मंचासीन अतिथियों का परिचय और स्वागत श्री मिलिंद देशपांडे ने किया। इस अवसर पर सत्र का संचालन कर रहे श्री अजय पतकी ने भारत रत्न महर्षि कर्वे का जीवन परिचय प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय परिषद बैठक में प्रथम उद्बोधन अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुंदरम द्वारा दिया गया। उद्बोधन के मुख्य बिंदु इस प्रकार है– स्वदेशी जागरण मंच की कार्यप्रणाली को युगानुकूल टेक्नोलॉजी के अनुसार परिवर्तन किया गया। आज हमारा अर्थ संग्रह पेपरलेस और कैशलेस किया जा चुका है। इसके अलावा स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम भी हुए हैं और चल रहे हैं। इन सभी अभियानों के फलस्वरूप आज हम जहां खड़े हैं, तो हम विनम्रता पूर्वक गर्व से कह सकते हैं कि–

1. हमारा भौगोलिक विस्तार हुआ है।
2. हमारा संगठनात्मक विस्तार हुआ है, चालीस प्रांतों के 620 ज़िलों में हमारी इकाईयां काम कर रही हैं।
3. विचार परिवार में हमारी प्रासंगिकता एवं स्वीकार्यता बढ़ी है। दशकों के बाद विचार परिवार में आर्थिक प्रस्ताव पारित हुआ और उसके क्रियान्वयन की वृहद योजना बनी। विभिन्न संगठनों ने इस योजना के समन्वय का दायित्व स्वदेशी जागरण मंच को प्रदान किया। विभिन्न अवसरों पर परमपूज्य सरसंघचालक जी, माननीय सरकार्यवाह जी व माननीय पूर्व सरकार्यवाह जी ने सार्वजनिक रूप से हमारे कार्यों की सराहना की और हमारे कार्यक्रमों में सहभागिता की।
4. नई दिल्ली में स्वदेशी शोध संस्थान के भवन का निर्माण कार्य व उसके 13 वर्टिकल्स के नीति शोध कार्य, दोनों में तेज़ी से प्रगति हो रही है। अनेक प्रकार का साहित्य निर्माण भी इस कार्यकाल में हुआ है।
5. 9 सत्र, 68 विद्वान वक्ता, 7 वाइस चांसलर महोदय, 2 केंद्रीय मंत्री, 2 माननीय सह सरकार्यवाह, एक माननीय पूर्व सह सरकार्यवाह, 14 संगठनों के संगठन मंत्री, प्रख्यात गीतकार श्री कैलाश खेर, 45 प्रांतों के 1350 प्रतिनिधियों की सहभागिता से नई दिल्ली में सम्पन्न तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला स्वावलंबी भारत अभियान में मील का पत्थर है।
6. माईएसबीए वेब पोर्टल, माईएसबीए एप, फ़ेसबुक, ट्विटर सहित अनेक माध्यमों से हमारी सोशल मीडिया में व डिजिटल पहुंच बढ़ी है।

7. 452 ज़िलों में रोज़गार सृजन केंद्र खुल चुके हैं और उन्हें व्यवस्थित करने का काम प्रगति पर है। शेष ज़िलों में भी केंद्र खोले जा रहे हैं।

श्री सुंदरम में आगे कहा कि मंच का गठन हुए 30 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 30 वर्षों भारत सहित दुनिया भर में अनेक आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हुए हैं। आने वाला समय और अधिक तीव्र गति से आने वाले परिवर्तनों का है। स्वाभाविक रूप से परिवर्तन चुनौती भी लाते हैं और इनके बीच अपार अवसर भी छुपे हुए होते हैं। हमें न केवल इन अवसरों को भांपना है, बल्कि इनका लाभ भी उठाना है। हमें गहरा आत्मावलोकन करना है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्निधारित करना है। देश को हमसे क्या आशा है? देश के सामने क्या चुनौतियां और अवसर हैं? इन सबके आलोक में हम आज वर्तमान में काम करेंगे। यही हमारा भविष्य का मार्ग रहेगा।

अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने भी उद्‌घाटन सत्र में कहा कि आज पुणे में बैठक हो रही है, इस जगह का सावरकर जी से भी गहरा नाता है। विदेशी सामान की होली जलाने का कार्य यहां के फर्ग्युसन कॉलेज की भूमि पर सावरकर जी द्वारा किया गया था। उन पर कॉलेज प्रशासन द्वारा 10 रुपये का अर्थ दंड भी लगा था और तिलक महोदय ने संपादकीय लिखकर इस अंग्रेजी कुकृत्य की निंदा एवं युवा सावरकर का उत्साहवर्धन किया था।

उन्होंने आगे कहा कि एक विद्यार्थी पढ़ाई के साथ–साथ कौशल विकास से संबंधित सभी कुछ सीख जाए, ऐसी गुरुकुल पद्धति पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी ने इस पुणे महानगर में निर्मित की, य़ह जीवंत स्वदेशी तीर्थ स्थान है। माननीय सुंदरम जी द्वारा दिया गया भाषण स्वदेशी जागरण मंच की 32 वर्षों की यात्रा का सुन्दरतम विवरण है और उसका लिखित स्वरूप भी उपलब्ध है, उसे हमें बार–बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि व हमारे कार्य को गति देगा।

श्री कश्मीरी लाल ने आगे कहा कि 2047 में भारत का स्वरूप कैसा हो, उसको कैसा बनाना है? इस विषय पर चर्चा कर आगामी रोड मैप तैयार करना होगा। आगरा के दयालबाग में पिछले 97 वर्षों से एक मंदिर बन रहा है, जब मंदिर की परिकल्पना की गई होगी तब पीढ़ी अलग रही होगी, वैसे ही हमने 2047 के स्वरूप के बारे मे हमे सोचना होगा।

इस अवसर पर श्रीमती शैलजा सांघे (स्मारिका में मुख्य भूमिका रखने वाली) ने स्वाबलंबी भारत अभियान की स्मारिका का मंचासीन अधिकारियों द्वारा विमोचन भी कराया गया। जिसकी डिजिटल कॉपी भी उपलब्ध रहेगी।

द्वितीय सत्र में स्वावलंबी भारत अभियान और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विभिन्न प्रांतों में आयोजित किए गए कार्यक्रमों और गतिविधियों का विवरण क्षेत्रानुसार वृत निवेदन का रहा। जिसमें दक्षिण क्षेत्र–श्री सत्यनारायण (क्षेत्र समन्वयक), दक्षिण मध्य क्षेत्र–डॉ. एस. लिंगामूर्ति (क्षेत्र समन्वयक), पश्चिम क्षेत्र–श्री रमेश भाई दवे (क्षेत्र संयोजक), मध्य क्षेत्र–श्री सुधीर दाते (सह क्षेत्र संयोजक), राजस्थान क्षेत्र–डॉ सतीश कुमार आचार्य (क्षेत्र संयोजक), उत्तर क्षेत्र–श्री राजेश गोयल (क्षेत्र समन्वयक), पश्चिमी उत्तर प्रदेश–डॉ. अमितेश अमित (क्षेत्र समन्वयक), पूर्वी उत्तर प्रदेश–अनुपम श्रीवास्तव (क्षेत्र समन्वयक), बिहार व झारखंड–अमरेंद्र सिंह (क्षेत्र समन्वयक), पूर्वी क्षेत्र–शत्रुघ्न तराई (क्षेत्र संयोजक), पूर्वोत्तर क्षेत्र–श्री दीपक शर्मा (त्रिपुरा) द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों का वृत्त प्रस्तुत किया।

स्वाबलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय समन्वयक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने आगामी 1 जून से 30 जून तक चलने वाले **'अर्थ संचय अभियान'** एवं पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा उनके प्रशिक्षण, 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस से संबंधित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय सह समन्वयक डॉ. राजीव कुमार ने अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार के 45 प्रांतों में 9 अगस्त, अगस्त क्रांति के दिन मुंबई से प्रारंभ होने वाले अखिल भारतीय प्रवास की विस्तृत जानकारी दी।

तृतीय सत्र में चर्चा हेतु दो विषय एवं एक प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद में कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा गया। सत्र की अध्यक्षता अखिल भारतीय संयोजक श्री. आर. सुंदरम ने की। मंच पर डॉ. अश्वनी महाजन, श्री धनपतराम अग्रवाल और अखिल भारतीय सह–संपर्क प्रमुख श्री अनिल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही।

श्री अनिल शर्मा ने "जी20 और भारत" विषय पर विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जी20, 10 विकसित और 10 विकासशील देशों का एक वैश्विक संगठन है, जिसकी बैठक की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। 'वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी एक परिवार' इसका ध्येय वाक्य है। जी–20 की बैठकों में वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू.एच.ओ, आई.एल.ओ, आई,एम,एफ, डब्ल्यू.टी.ओ. आदि यह सभी संस्थाएं स्थाई सदस्य के रूप में रहती है। जी20 में 2 आयाम होते हैं और विभिन्न प्रकार के ट्रेक होते हैं। पिछले वर्ष इसकी बैठक इंडोनेशिया में हुई और अगली बार यह बैठकें ब्राजील में संपन्न होगी।

इस सत्र में डॉ. अश्वनी महाजन ने "रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने" के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जुलाई 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक परिपत्र के माध्यम से भारतीय रुपये में वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए निपटान की अनुमति दी। यह यूक्रेन और रूस युद्ध और रूस और ईरान को भुगतान के लिए

प्रस्ताव

"2047 का भारत"– एक स्वदेशी परिप्रेक्ष्य

हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए "स्वाधीनता का पर्व" मना रहा है। भारत को पूर्ण रूप से विकसित देश बनाने हेतु आगामी 25 वर्ष अमृत बेला के बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2047 के भारत की दृष्टि से हमें मूल्याद्धिष्ठित आर्थिक प्रगति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था तथा उन्नत जीवन– स्तर हेतु ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना होगा, जैसा विदेशी आक्रमणों से पहले 17वीं शताब्दी में हुआ करता था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 25 प्रतिशत योगदान देता था। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हमारी जनसंख्या हमारी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का एक महत्वपूर्ण साधन है।

भारत अब तक गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के ऋण के बोझ और भ्रष्टाचार तथा उत्पादन क्षेत्र में कमी व बढ़ते राजकोषीय तथा चालू खाते में घाटे आदि समस्याओं का समाधान करने का सतत् प्रयास कर रहा है। 2047 के भारत को एक सुदृढ़ उत्पादन तंत्र का निर्माण करना चाहिए और अमेरिकी डॉलर एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। भारतीय मुद्रा को प्रोत्साहित करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। चालू खाता अधिशेष के माध्यम से बनाए जाने वाले विदेशी मुद्रा भंडार के साथ एक ऋण मुक्त देश हमारा भारत बने, यह प्रयास करते रहना होगा।

पिछले कुछ सालों से भारत में उपभोग आधारित विकास की तरफ रूझान देखा जा रहा है, लेकिन वृद्धि और विकास में बढोत्तरी लाने के लिए एक नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है, जो निवेश आधारित होनी चाहिए।

हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि हमारी जनसंख्या हमारी अर्थव्यवस्था ही संपन्नता का एक महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान ज्ञान व तकनीकी के युग में संपूर्ण विश्व पांचवी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमारी युवा शक्ति नवीनतम तकनीक के उपयोग से इस प्रगति का नेतृत्व कर सकती है। प्रगति के इस मार्ग में हमें वसुधैवकुटुम्बकम् के आधार पर "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" इस मूल मंत्र के साथ भौगोलिक, राजनीति, वैश्विक आर्थिक ढांचा बनाने में प्रभावी नेतृत्व करना होगा। 2047 के भारत को न केवल एक मजबूत आर्थिक शक्ति, बल्कि एक मजबूत सैन्य शक्ति भी होना चाहिए। नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली के साथ अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को दृढ़ता के साथ सुरक्षित करना होगा। भारत का कोई भी नागरिक गरीबी रेखा के नीचे न हो व प्रत्येक कार्यकुशल व्यक्ति को स्वरोजगार का योग्य अवसर मिले, ऐसा अनुकूल वातावरण निर्माण करना होगा। न्यायपूर्ण व संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रसार में जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कर युवा शक्ति को प्रेरित कर, उनकी उत्पादकता बढ़ानी होगी।

हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देनी होगी और बौद्धिक संपदा एवं नवाचार को बढावा देने के लिए अपने बौद्धिक संसाधनों का उपयोग करना होगा, ताकि विदेशी वस्तुओं और प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता कम से कम हो और हम स्वावलंबी हो सकें। हम भारतवासी सतत विकास, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और संयमित उपभोग के सिद्धांतों का पालन करके पर्यावरण की रक्षा और धरती माता के पोषण में विश्वास करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के सभी पांच तत्वों के प्रदूषण की समस्या को जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से मुक्त किया जाना चाहिए, जिससे स्वदेशी तकनीक और हमारे संसाधन के आधार पर डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमारी पहल से वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ सकें।

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद यह प्रस्तावित करती है कि हमें विज्ञान और आर्थिक विकास के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना चाहिए, एकात्म मानववाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए विज्ञान वरदान बना रहे, अभिशाप ना बने। 2047 के भारत की योजना एक ऐसे विकास का संकल्प है, जो ग्राम रोजगार व पर्यावरण केंद्रित होगा और मूल्यों, नैतिकता के सिद्धांतों, सहकारिता और विकेंद्रीकरण पर आधारित होगा।

डॉलर के उपयोग पर अमेरिकी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में एक रणनीतिक निर्णय था। एक अन्य कारण भारतीय निर्यात को बढ़ावा देकर भारतीय रुपये को कमजोर करने का समर्थन करना था, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। दिसंबर 2022 में भारत ने पहली बार भारतीय रुपये में कच्चे तेल के आयात के लिए रूस को भुगतान किया। इससे भारतीय रुपए पर बाजार से लगातार बढ़ती दर पर डॉलर खरीदने का कुछ दबाव कम हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय के परिणामस्वरूप दुनिया के कई देश जो भारत से आयात करने में रुचि रखते थे और डॉलर की कमी के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, अब वे अपने आयात के लिए भारतीय रुपए में भुगतान कर सकते हैं। भारतीय रुपये में व्यापार के निपटान की सुविधा के लिए, अब तक, भारतीय बैंकों ने यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इज़राइल, रूस और संयुक्त अरब अमीरात सहित 19 देशों के साथ 'विशेष वोस्ट्रो खाते' खोले हैं।

'भारत@2047' के प्रस्ताव का वाचन श्री धनपतराम अग्रवाल ने किया। इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के साथ राष्ट्रीय सभा में पारित किया गया।

चतुर्थ सत्रः इस सत्र में मंच पर श्री कश्मीरी लाल, श्री अरुण ओझा और प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रही। श्री अरुण ओझा ने "स्वदेशी जागरण मंच की

प्रारंभिक सांगठनिक रचना" को स्पष्ट करते हुए बताया कि स्वदेशी जागरण मंच कोई संस्था नहीं, एक अभिनव प्रकार का संगठन है, यह जन जागरण का क्रांतिकारी आंदोलन है' जिसे राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने वैश्विक परिदृश्य और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण के विरुद्ध खड़ा किया। प्रारंभ में इसमें केंद्रीय समिति, केंद्रीय संचालन समिति और राष्ट्रीय परिषद के नाम से कार्यकर्ताओं को जोडते हुए कार्य प्रारंभ हुआ। क्योंकि हम मंच हैं, हम आंदोलन हैं तो पूरे देश में संगठन का निर्माण कैसे होगा? संगठन निर्माण की 3 सीढ़ियां हैं– 1. व्यक्तिगत जुड़ाव, 2. संस्थागत जुड़ाव व 3. विचारधारा से जुड़ाव। हमें कार्यकर्ताओं को पहले व्यक्तिगत जुड़ाव के माध्यम से, फिर उन्हें संगठन या संस्था के माध्यम से और अंत में मूल विचारधारा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।

कार्यकर्ता भी दो प्रकार के होते हैं– 1. पूर्णकालिक, 2. गृहस्थी। पूर्णकालिक भी दो प्रकार के हैं– एक, प्रचारक जीवन जीने वाले और दूसरे, अंशकालिक संगठन का कार्य करने वाले।

समय–समय पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का कहना था कि "जब समाज के श्रेष्ठ वर्ग का समय बर्बाद होता है, तो समाज का काम होता है"। कार्यकर्ताओं के लिए वे कहते थे कि "यू आर फूल्स" पागलपन और जुनून की हद तक पहुंचने पर ही स्वदेशी का कार्य खड़ा किया जा सकता है।

इसी सत्र में श्री कश्मीरी लाल का संगठन की अवधारणा विषय पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उद्‌बोधन हुआ। उन्होंने कहा– संगठन क्या? और क्यों? समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह, जो एक उद्देश्य और एक लक्ष्य के साथ विभिन्नता वाले व्यक्तित्व को जोड़ते हुए एक निश्चित कार्यक्रम और एक रचना में सबके लिए जो कार्य करता है, वही संगठन है। यदि साथ के साथ दायित्वों की घोषणा व उसकी मूल्यांकन नहीं होता तो कार्य में ठहराव आ जाता है।

प्रारंभ में संगठन और संस्था खड़ा करना आसान है परंतु उसे नियमित रूप से लम्बे समय तक संचालित करना और चलाना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी इसके लिए कार्यकर्ताओं के लिए 'देव दुर्लभ टोली' शब्द का प्रयोग करते थे।

दत्तोपंत जी स्वयं एक कुशल संगठन शिल्पी थे। उनका कहना था कि संगठन का कार्य आत्म केंद्रित होकर कार्य नहीं करना, बल्कि कार्यकर्ता को खड़ा करना है। कार्यकर्ता को स्वयं के साथ नहीं जोड़ना, बल्कि संगठन और विचार के साथ जोड़ना, जिस तरीके से बौद्ध धर्म के लिए 3 शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं– बुद्धम, शरणम, गच्छामि। धम्मम, शरणम, गच्छामि। संघम, शरणम, गच्छामि। उसी प्रकार पहले, व्यक्तिगत जुड़ाव, फिर संस्था से जुड़ाव और फिर विचारधारा के साथ जुड़ाव करना।

श्री कश्मीरी लाल ने आगे कहा कि संगठन में कार्य करते हुए हमें कार्यकर्ता के केवल गुणों का ही ध्यान करना चाहिए। अच्छी बातों को ही ध्यान में रखेंगे, तो अपना भी आत्मबल बढ़ेगा और कार्यकर्ता का भी आत्मबल बढ़ेगा। हम सब मंच में अपनी–अपनी भूमिका तय करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए कार्य विस्तार करते चलें।

पांचवां सत्रः इस सत्र में स्वावलंबी भारत अभियान को सफल बनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के समन्वय में सम्मिलित सभी संगठनों के अखिल भारतीय दायित्व वान कार्यकर्ता तरंग माध्यम से जुड़े।

विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं का परिचय होने के बाद अभियान के अखिल भारतीय समन्वयक माननीय भगवती प्रकाश शर्मा जी ने "हमारा समन्वय– हमारी शक्ति" को स्पष्ट करते हुए बताया कि स्वावलंबी भारत अभियान में हमारी समन्वय शक्ति से भारत भूमि पर विकास की आकाश गंगा का संगम होगा।

भारत के पास सर्वाधिक युवा शक्ति है' सर्वाधिक कृषि भूमि हैं' सर्वाधिक लघु एवं कुटीर उद्योग है ऐसी स्थिति में स्वावलंबी भारत अभियान और 2047 तक के अमृत काल में जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तब भारत बेरोजगारी मुक्त एवं समृद्धि युक्त बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका होगा। आज सभी संगठन समन्वय के साथ–साथ अपने– अपने स्तर पर भी स्वावलंबी भारत अभियान में रोजगार के प्रकल्प संचालित करने ग्राम स्वरोजगार के लिए भाव जागरण के लिए लगे हुए हैं! इस अभियान के माध्यम से देश के युवाओं में उद्यमिता के अंकुर को प्रस्फुटित करना' मानसिकता परिवर्तन के कार्यक्रम करना' भाव जागरण के लिए समाज में जाना और युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए जिला स्थित जिला रोजगार सृजन केंद्र को सक्रिय रूप से तैयार करना होगा ।हमारी समन्वय शक्ति से निश्चित रूप से हम गरीबी मुक्त और समृद्धि युक्त भारत का निर्माण करने में सफल होंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के श्री राजीव सिजारिया द्वारा आगामी 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस पर विद्यार्थी परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम और उसकी जानकारी तरंग माध्यम से प्रदान की।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने "2047 में कैसा होगा भारत विषय" पर समृद्ध भारत, सशक्त भारत और भारत की जनसंख्या, भारत के लिए समस्या नहीं वरदान हो सकती है। इस विषय पर प्रस्तावना रूप 5 बिन्दु सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखे– 1.

युवा, स्वस्थ, शिक्षित व योग्य–जनसंख्या, 2. पूर्ण रोजगार युक्त, पर्यावरण हितैषी, विकेंद्रीकृत, उन्नत–अर्थव्यवस्था, 3. सशक्त, सुरक्षित अजेय भारत, 4. विज्ञान प्रौद्योगिकी में अग्रणी व 5. जीवन मूल्य व वैश्विक दृष्टिकोण, श्री सतीश कुमार ने इस कल्पना की प्रस्तुति की और सुझाव भी मांगे।

छठा सत्रः इस सत्र में डिजिटल तन्त्र माईएसबीए, अर्थ संचय अभियान विषय पर विस्तृत चर्चा हुई।

मंच पर श्री सतीश कुमार, माईएसबीए प्रमुख हार्दिक सोमानी, वित्त आयाम के प्रमुख श्री सतीश चावला व श्री आर. सुंदरम की गरिमामय उपस्थिति रही। सत्र का संचालन अभियान की अखिल भारतीय महिला सह–समन्वयक श्रीमती अर्चना मीना ने किया।

एलईडी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हार्दिक सोमानी ने कैशलेस और पेपर लेस अभियान की विस्तार से जानकारी दी। तैयार किए गए डिजिटल लिंक से विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा मोबाइल फोन द्वारा लिंक का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान करवाया ताकि कार्यकर्ताओं को अपने–अपने क्षेत्र में अर्थ संचय के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके। उन्होंने एक जिले के लिए 3 से 5 लाख रुपए के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीके बताए।

श्री सतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि केवल सोशल मीडिया के माध्यम से यह अर्थ संग्रह अभियान पूर्ण नहीं होगा, इसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों, अपने घर परिवार से प्रारंभ करते हुए टोलियों का गठन करना और त्रिस्तरीय टोलियों के गठन के बाद व्यक्तिगत रूप से समाज के भामाशाह और दानदाताओं से सम्पर्क कर इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।

सप्तम सत्रः यह सत्र क्षेत्रानुसार आगामी कार्य योजना, अर्थ संचय अभियान, महिला कार्य, स्वदेशी मेला और 9 अगस्त से 2 अक्टूबर तक प्रारंभ होने वाले श्री सतीश कुमार के प्रवास के संबंध में क्षेत्र और प्रांतों के कार्यकर्ताओं के साथ अलग–अलग स्थानों पर संचालित हुआ।

- दक्षिण और दक्षिण मध्य क्षेत्र की संयुक्त बैठक का संचालन श्री सत्यनारायण ने किया तथा बैठक में श्री आर सुंदरम की उपस्थिति रही।
- पश्चिम क्षेत्र की बैठक में श्री जितेन्द्र गुप्त एवं डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी की उपस्थिति रही और बैठक का संचालन श्री रमेश भाई दवे ने किया।
- मध्य क्षेत्र की बैठक में डॉ. अश्वनी महाजन की उपस्थिति रही और बैठक का संचालन सह–क्षेत्र संयोजक श्री सुधीर दाते ने किया।
- राजस्थान क्षेत्र में प्रो. भगवती प्रकाश की उपस्थिति और बैठक का संचालन डॉ सतीश कुमार आचार्य ने किया।
- उत्तर क्षेत्र की बैठक में डॉ राजकुमार मित्तल की उपस्थिति और बैठक का संचालन उत्तर क्षेत्र संयोजक श्री राजेश गोयल ने किया।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक का संचालन डॉ. अमितेश अमित ने किया और श्री अजय पत्की की उपस्थिति रही।
- बिहार–झारखंड की बैठक का संचालन श्री अमरेंद्र सिंह ने किया और इस बैठक में श्री अरुण ओझा की उपस्थिति रही।
- पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र की बैठक का संचालन री शत्रुघ्न तरई ने किया और डॉ. धनपत राम अग्रवाल की उपस्थिति रही।

समारोप सत्रः सर्वप्रथम राष्ट्रीय परिषद की व्यवस्थाओं में लगे हुए पुणे महानगर के समस्त कार्यकर्ताओं का परिचय श्री मुकुल वैद्य ने कराया। पूरे देशभर से आए हुए समस्त कार्यकर्ता बंधुओं ने करतल ध्वनि से व्यवस्थाओं में लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया।

श्री शशांक मणि (जागृति यात्रा) ने उद्यमिता का महत्व विषय पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि उद्यमिता एक प्रक्रिया है, पर यह वास्तव में एक मौलिक सोच भी है। स्वरोजगार का यह काम गांव में जिला स्तर पर और छोटे–छोटे शहरों में होना चाहिए। इन सबमें नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, सामान्य व्यक्ति जब नवाचार करता है तो उससे उद्यमिता के नए–नए आयाम सृजित होते हैं। अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी ने भी इस सत्र में नागरिक कर्त्तव्य के बारे में जानकारी दी।

श्री कश्मीरी लाल ने समारोप सत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में और संगठन में सफलता का मूल मंत्र लक्ष्य पर फोकस करना है। सामान्यतया जब तक दायित्व रहता है तब तक हम संगठन में काम करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने महात्मा हंसराज जी का उदाहरण देते हुए बताया कि दायित्व से मुक्त होने के बाद भी महात्मा हंसराज जी ने बड़ा कार्य करके बताया।

हमें पारस पत्थर के समान और एक से एक दीप जलाते हुए इस कार्य को बढ़ाना है। मातृशक्ति के कार्य को बढ़ाने का भी आह्वान किया। श्री कश्मीरी लाल ने श्री आर. सुंदरम के आदेशानुसार नवीन दायित्वों की भी घोषणा की।

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने बताया कि 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस का जब आयोजन होगा और उसके बाद जब युवाओं में सोच परिवर्तन का बड़ा सैलाब आएगा तो वह सब स्वावलंबी भारत अभियान के मूल केंद्र जिला रोजगार सर्जन केंद्र पर उपस्थित होंगे। हमें उनकी आशा और विश्वास पर मार्गदर्शन देते हुए भारत को उद्यमिता की

ओर मोड़ना होगा। इस अवसर पर श्री आर सुंदरम ने स्वदेशी जागरण मंच के कार्य का विस्तार करने का आह्वान करते हुए अखिल भारतीय स्तर की घोषणाएं की एवं राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय परिषद का समापन हुआ।

नवीन दायित्व

- श्री कमल तिवारी – अखिल भारतीय सह कोष प्रमुख (पूर्व में दिल्ली प्रांत सह संयोजक)।
- सीए संजीव माहेश्वरी – राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य (पूर्व में राष्ट्रीय सह–कोष प्रमुख)।
- श्री लक्ष्मण भावसिंहका – पूरे केंद्रीय कार्यालय प्रमुख (दिल्ली)
- श्री साकेत राठौर – भोपाल मेला समिति सह–प्रमुख
- श्री सुब्रत चाकी – मेला समिति पूर्णकालिक
- श्री रविन्द्र सोलंकी – मेला केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख

क्षेत्र एवं प्रान्तीय नवीन दायित्व

दक्षिण क्षेत्र *– दक्षिण तमिलनाडु*

- श्री वरदराजन – राष्ट्रीय परिषद सदस्य
- श्री रमेश – मदुरै विभाग संयोजक

उत्तर तमिलनाडु

- डॉ. शेषाद्रि – राष्ट्रीय परिषद सदस्य

दक्षिण मध्य क्षेत्र *– दक्षिण कर्नाटक*

- रश्मी विजय कुमार – प्रांत सह संयोजक (कर्नाटक दक्षिण)

आन्ध्र प्रदेश

- श्री राजेश – विजयवाड़ा व गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) दोनों विभागों के संगठक

पश्चिम क्षेत्र

- श्री राजीव क्षीरसागर – पूर्व में महाराष्ट्र प्रदेश संगठक अब संघ योजना से कार्य करेंगे।

पश्चिम महाराष्ट्र प्रान्त

- श्री मुकुल वैद्य – प्रान्त सह संयोजक (पश्चिम महाराष्ट्र)

कोकण प्रांत

- श्री माधव नायर – प्रान्त संयोजक (कोकण)

गुजरात प्रान्त

- श्री चैतन्य भट्ट – गुजरात प्रदेश (गुज़रात प्रान्त एवं सौराष्ट्र प्रान्त) के प्रचार प्रमुख रहेंगे, पहले गुजरात प्रांत संयोजक थे।
- श्री हसमुख भाई ठाकर – प्रान्त संयोजक
- श्री करन सिंह गौड़ – प्रान्त सह संयोजक

सौराष्ट्र प्रांत

- श्री यशभाई जयसानी (राजकोट) – प्रान्त सह संयोजक
- सीए हार्दिक भाई व्यास (राजकोट) – सौराष्ट्र प्रांत विचार विभाग प्रमुख

मध्य क्षेत्र

- श्री रामप्रकाश माहेश्वरी – क्षेत्र कोष प्रमुख

छत्तीसगढ़ प्रान्त

- श्री मोहन पंवार – माइक्रोफाइनेंस, स्वदेशी भवन एवं संगवारी प्रोजेक्ट प्रमुख (पूर्व में छत्तीसगढ़ प्रान्त संयोजक थे)।
- श्री जगदीश पटेल – छत्तीसगढ प्रान्त संयोजक

राजस्थान क्षेत्र

- श्री अनिल वर्मा – जोधपुर प्रांत के संयोजक के साथ ही राजस्थान क्षेत्र के अभियान के क्षेत्र समन्वयक के दायित्व का भी निर्वाह करेंगे।

उत्तर क्षेत्र *– हरियाणा प्रान्त*

- श्रीमती सुनीता भरतवाल – प्रान्त सह संयोजक
- श्री संजय – सह सम्पर्क प्रमुख

पंजाब प्रान्त

- श्री विनय कुमार – पंजाब प्रांत संगठक व हिमाचल तथा जम्मू–कश्मीर प्रांतों के संपर्क प्रमुख भी रहेंगे।
- श्री चन्द्रशेखर – प्रांत कार्यकारिणी सदस्य (पूर्व में प्रान्त संयोजक)
- श्री अरविन्द शर्मा – प्रान्त संयोजक (पूर्व में प्रान्त सह–संयोजक)

हिमाचल प्रदेश

- श्री ललित कुमार – प्रांत कार्यकारिणी सदस्य (पूर्व में प्रान्त सह संयोजक)
- श्री ओंकार – प्रांत कार्यकारिणी सदस्य (पूर्व में प्रांत संघर्षवाहिनी प्रमुख एवं प्रांत सह–समन्वयक)

उत्तराखंड प्रांत

- श्री सुरेन्द्र सिंह – क्षेत्र संपर्क प्रमुख (पूर्व में प्रांत संयोजक)
- श्री रामकुमार चौधरी – प्रांत संयोजक (पूर्व में प्रांत सह संयोजक)

दक्षिण बिहार

- डॉ संजीव – दक्षिण बिहार प्रान्त सह संयोजक

उड़ीसा पूर्व प्रांत

- श्री प्रसन्ना चटृराय – प्रांत विचार विभाग प्रमुख
- श्री रबिन्द्र सेट्ठी – प्रांत संपर्क प्रमुख
- श्रीमती लक्ष्मी प्रिया साहू – प्रांत महिला प्रमुख
- करूशना प्रिया बेहरा – कटक विभाग संयोजक

पूर्वोत्तर क्षेत्र

- प्रो. तरनी डेका – उत्तरी आसाम के प्रांत संयोजक तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अभियान क्षेत्र समन्वयक।

❑❑

उद्यमशीलता से होगा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण – स्व.जा.मं

पुणे में स्वदेशी जागरण मंच की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद बैठक में देश के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर उन्हें उद्यमी बनाकर सन् 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया गया। दो दिवसीय बैठक का समापन रविवार को महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के सभागार में हुआ। मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन, पश्चिम क्षेत्र सह संयोजक प्रशांत देशपांडे व पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत संयोजक हेमंत साठे ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बैठक के संबंध में जानकारी प्रदान की।

डॉ. महाजन ने कहा कि देश के युवाओं में प्रतिभा है और उनकी प्रतिभा को अवसर प्रदान करने हेतु जिला रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। देश के 756 जिलों में केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 430 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं. इन्हें सु.ढ करने हेतु एक जून से 30 जून तक सघन संपर्क अभियान चलाया जाएगा। साथ ही माईएसबीए डिजिटल अभियान को भी गति दी जाएगी। स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

आगामी 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोग से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। नवंबर और दिसंबर महीने में देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर स्वदेशी स्वावलंबन मेलों का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में 38 प्रांतों के 230 पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें 38 महिलाएं थी। साथ ही इसमें 16 संस्थाओं का प्रतिनिधित्व रहा. बैठक में मंच की अगले एक वर्ष के कार्य की रूपरेखा तैयार की गई। स्वदेशी जागरण मंच की गतिविधियों में परसिस्टेंट टेक्नोलॉज़ीज़, जागृति और सेपियो एनालिसिस जैसी कंपनियों और संगठनों का साथ मिलने की जानकारी भी इस अवसर पर दी गई।

बैठक के उपलक्ष्य में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से दो निवेदन जारी किए गए। पहले निवेदन में कहा गया है कि भारत को 2047 में एक कुशल विनिर्माण प्रणाली बनानी चाहिए और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट को रोकना चाहिए। भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देकर भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए।

दूसरे निवेदन में कहा गया कि जी–20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए आज दुनिया के सामने स्थित समस्याओं का समाधान खोजने का एक अवसर है और भारत को इस मंच का उपयोग विश्व व्यापार संगठन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में आम सहमति बनाने के लिए करना चाहिए।

दो दिवसीय बैठक में कुल सात सत्र हुए, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमें विज्ञान और आर्थिक प्रगति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना चाहिए। एकात्म मानववाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए विज्ञान अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान होना चाहिए। वर्ष 2047 के लिए भारत का लक्ष्य एक विकास संकल्प है जो ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण पर केंद्रित है. यह मूल्यों, नैतिकता के सिद्धांतों, सहयोग और विकेंद्रीकरण पर भी आधारित होगा।

https://vskbharat.com/self-reliant-india-will-be-built-by-2047-by-promoting-entrepreneurship-swadeshi-jagran-manch/

आयात–निर्यात के लिए रुपये में बढ़े भुगतान की सुविधाः स्व.जा.मंच

अंतरराष्ट्रीय व्यापार (आयात–निर्यात) में रुपये में भुगतान की सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डॉलर, यूरो) की बचत होगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये को मजबूती और नई पहचान मिलेगी। जिन देशों से भारत आयात–निर्यात करता है उन देशों से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिये ऐसा किया जा सकता है। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक में सरकार को यह सुझाव दिया गया है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रुपये में व्यापार निपटान को मंजूरी देने के ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और उपाय किए जाने चाहिए। इनमें अधिक से अधिक देशों को व्यापार मुद्रा के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करके ऐसा कर सकता है। इसके अलावा, व्यापार

के लिए रुपये के उपयोग को आसान बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें बाजार में रुपये की तरलता बढ़ाने और व्यवसायों के लिए रुपया खाते खोलना आसान बनाना शामिल हो सकता है।

3–4 जून को हुई बैठक में सरकार से यह भी आग्रह किया गया कि भुगतान संबंधी उपायों के अलावा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भी रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयास होने चाहिए। इसके तरहत विदेशी निवेशकों को रुपये–मूल्यवर्गित संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। साथ ही भारत रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठा सकता हैः–

– रुपया आधारित मजबूत बांड बाजार का विकास करना। यह व्यवसायों को निवेश विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा और उनके लिए रुपये में पूंजी जुटाना आसान बना देगा।
– पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में रुपये के प्रयोग को बढ़ावा देना। इससे भारत को इन देशों के साथ व्यापार के लिए विदेशी मुद्राओं के उपयोग की आवश्यकता को कम करने में मदद मिलेगी।
– अन्य देशों के साथ रुपये–मूल्य वाले व्यापार के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित करने के लिए काम किया जाए। इससे व्यवसायों के लिए उन देशों के साथ रुपये में व्यापार करना आसान हो जाएगा जिनका भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं है।

स्वेदशी जागरण मंच का कहना है कि इन कदमों को उठाकर भारत रुपये को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मुद्रा बनाने में मदद कर सकता है। यह डॉलर पर भारत की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके कई लाभ मिल सकते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को डॉलर के मूल्य में उतार–चढ़ाव से बचाने में मदद करेगा और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आयात–निर्यात के लिए रुपये में भुगतान की अनुमति जुलाई 2022 में दी थी। रूस–यूक्रेन –दइेच;युद्ध के चलते अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए रूस को भुगतान के लिए यह एक रणनीतिक निर्णय था। दिसंबर 2022 में भारत ने पहली बार कच्चे तेल के आयात के लिए रुपये में रूस को भुगतान किया। इस फैसले से दुनिया के कई देश जो भारत से आयात करने में रुचि रखते थे और डॉलर की कमी के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं थे अब वे अपने आयात के लिए रुपये में भुगतान कर सकते हैं। रुपये में भुगतान की सुविधा के लिए अब तक भारतीय बैंकों ने ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रूस और संयुक्त अरब अमीरात सहित 19 देशों के साथ 'विशेष वोस्ट्रो खाते' खोले हैं।

https://www.ruralvoice.in/national/india-should-increase-facility-of-payment-in-rupees-for-import-export-swadeshi-jagran-manch-gave-these-suggestions.html

सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

बीते कैलेंडर ईयर यानी 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पहली बार 3.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 3.50 लाख करोड़ डॉलर (288 लाख करोड़ रुपए) से ऊपर निकल गया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जी–20 अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन इसके लिए कुछ सुधारों की जरूरत होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में भारतीय जीडीपी 3.18 लाख करोड़ डॉलर यानी 263.50 लाख करोड़ रुपए की थी।

बहरहाल, मूडीज ने एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि ब्यूरोक्रेसी विभिन्न लाइसेंस लेने और बिजनेस स्थापित करने की प्रक्रिया धीमी कर सकती है। इसे प्रोजेक्ट की अवधि और लागत बढ़ा सकती है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा, 'निर्णय लेने में लेट लतीफी की वजह से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की रफ्तार कम कर देगी। खास तौर तब, जब एशिया–प्रशांत की अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, मसलन इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ भारत तगड़ी प्रतिस्पर्धा में है।'

मूडीज के मुताबिक, भारत में बड़ी और पढ़ी लिखी वर्कफोर्स है। ऐसे में छोटे परिवार बढ़ेंगे। साथ ही तेज शहरीकरण से घर, सीमेंट और कार की डिमांड बढ़ेगी। मूडीज के मुताबिक, भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च स्टील और सीमेंट सेक्टर्स के लिए मददगार होगा, जबकि नेट–जीरो एमिशन हासिल करने की चाहत अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देगी। मूडीज ने ये भी कहा कि इन सेक्टरों में भारत की क्षमता 2030 तक चीन से कम रहेगी।

जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक

है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है, तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है।

https://money.bhaskar.com/business/news/india-gdp-growth-rate-update-moodys-rating-on-indian-economy-131321420.html

खाद्य महंगाई पर मंडरा रहा अल नीनो का संकट

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में लगातार तीसरे माह भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर पर है, लेकिन आरबीआई की चिंताएं कम नहीं हुई है। खासकर मानसून और अल नीनो के संभावित प्रभाव का संकट मंडरा रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में खाद्य महंगाई पर देखने को मिल सकता है।

इक्रा के वरिष्ठ अर्थशास्त्री राहुल अग्रवाल के मुताबिक, महंगाई में गिरावट अच्छा संकेत है। फिर भी इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति पर कमजोर मानसून के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं भी उभर रही हैं। मानसून की शुरुआत में देरी हुई है और देश भर में वर्षा जून 2023 में अब तक कम रही है। साथ ही इस साल अल नीनो की स्थिति के विकास पर भी नजर रखने की जरूरत रहेगी क्योंकि इससे खराब मानसून हो सकता है और खरीफ की पैदावार और रबी की बुआई पर असर पड़ सकता है। इस तरह फसल उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है।

रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को मामूली घटाकर 5.1 फीसद कर दिया है। पिछली बैठक में इसके 5.2 फीसद पर रहने का अनुमान लगाया गया था। इस साल अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी के 6.4 फीसद से घटकर 4.7 फीसद पर आ गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि खुदरा मुद्रास्फीति अब भी चार फीसद के अनिवार्य लक्ष्य से ऊपर है और चालू वित्त वर्ष के बाकी समय में भी ऐसा रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति में स्थायी कमी के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "मुद्रास्फीति पर लगातार नजदीकी और सतर्क नजरिया बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि मानसून और अल नीनो का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। हमारा लक्ष्य टिकाऊ तरीके से मुद्रास्फीति को चार फीसद से नीचे बनाए रखना है।"

भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल, यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) भी कहते हैं। वहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) यानी थोक मुद्रास्फीति का अर्थ उन कीमतों से होता है, जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। यह कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती हैं।

https://www.livehindustan.com/business/story-effect-of-weather-on-inflation-el-nino-crisis-looming-over-food-inflation-8298246.html

दो हजार के आधे नोट बैंकों में लौटे, 30 सितंबर तक अधिकतर हो जाएंगे वापस

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि चलन में मौजूद दो हजार रुपये के कुल नोटों में से लगभग 50 फीसद बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने इन नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार रुपये के नोट चलन में थे।

शक्तिकांत दास ने बताया कि नोट वापस लेने की घोषणा के बाद अबतक 1.80 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। वापस आए कुल नोटों में से करीब 85 फीसद नोट बैंक खातों में जमा किए जा रहे हैं, जबकि बाकी नोटों को छोटे मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने पिछले महीने ही कहा था कि 2,000 के नोटों को चलन से हटाने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर बहुत सीमित असर होगा। चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 2,000 के नोट का हिस्सा सिर्फ 10.8 फीसद है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि 30 सितंबर की समयसीमा तक 2,000 के ज्यादातर नोट बैंकों में वापस आ जाएंगे। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वो तय समय के भीतर अपने नोट बैंकों में जमा कर दें या फिर बदल लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय बैंक 500 रुपए के नोटों की वापसी या फिर 1000 रुपए के नोट लाने पर भी कोई विचार कर रहा है, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। न ही उनका कोई ऐसा इरादा है। ❑❑

https://www.livehindustan.com/business/story-half-of-2000-notes-returned-to-banks-most-will-be-returned-by-september-30-8280965.html

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

प्रांतीय कार्यशालाएं व विचार वर्ग

सचित्र झलक

काशी प्रांत

मध्य बंगाल प्रांत

त्रिपुरा प्रांत

ब्रज प्रांत

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जून 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

राष्ट्रीय परिषद बैठक

पूणे, महाराष्ट्र (3–4 जून, 2023)

सचित्र झलक

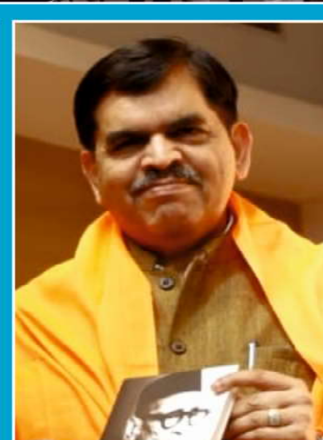

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती